सच बोलने की हिम्मत

राजधानी चौपाल

RNI No. HARHIN/25/A3341

अंक : 15 | वर्ष : 01 | साप्ताहिक (22 से 28 अप्रैल 2026) | पृष्ठ 8 | मूल्य : 5/- रुपये | E-mail : rajdhanichoupal@gmail.com

राजधानी चौपाल
समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...
94169-26329
93068-13001

बंगाल में मोदी बोले- टीएमसी का दीया बुझने वाला : शाह ने कहा- अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा

कोलकाता (राजधानी चौपाल)| पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम ने महिला आरक्षण पर कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा। बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। बंगाल में गुरुवार को पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ है। दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे।

पीएम ने कहा- टीएमसी ने 15 साल में बंगाल की पहचान खत्म की : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 15 साल में टीएमसी सरकार ने बंगाल की पहचान को खत्म कर दिया है। यहां घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। वे बंगाल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। एक तरफ टीएमसी का भ्रष्टाचार है, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों का अत्याचार। बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा, जब टीएमसी पूरी तरह पराजित होगी और भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता में आएगी। यहां बैठी TMC सरकार वंचित वर्ग के खिलाफ है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बाधा डाल रही है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक के इलाज का खर्च मोदी सरकार उठाती है, लेकिन टीएमसी ने इस योजना को बंगाल में रोक रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी टीएमसी सरकार घपला कर रही है।

पीएम मोदी ने कहा- बंगाल को चाहिए टीएमसी से मुक्ति : पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को चाहिए टीएमसी से मुक्ति चाहिए। टीएमसी के डर से मुक्ति, टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्ति, टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति, बेटियों पर अत्याचार से मुक्ति, मजबूरन पलायन से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति और अवैध कब्जों से मुक्ति। बंगाल की गरिमा लौटाने और इसे फिर अवसरों की भूमि बनाने के लिए यह मुक्ति बहुत जरूरी है। बंगाल की महिलाएं कह रही हैं कि वे राज्य में टीएमसी सरकार बदलेंगी।

टीएमसी महिला विरोधी पार्टी है, जबकि बीजेपी महिला-नेतृत्व वाले विकास के मॉडल पर काम करती है। जिस मां ने अपनी बेटी को पढ़ाया, वही बेटी टीएमसी के जंगलराज की शिकार हो गई, उसे बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। संदेशखाली की पीड़िताओं को भी नेतृत्व का मौका दिया गया है।

मोदी की स्पीच के 4 पॉइंट्स, कहा...

- बंगाल को टीएमसी से आजादी चाहिए। टीएमसी के डर से आजादी, टीएमसी के भ्रष्टाचार से आजादी, टीएमसी के सिंडिकेट से आजादी, बेटियों पर अत्याचार और बेरोजगारी से आजादी।
- टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, लेकिन पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्यज फहराना है।
- जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर न निकलने की सलाह देती है। टीएमसी नहीं चाहती कि महिलाएं सपने देखें।
- 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं पर हुए सभी अत्याचारों की फाइलें खोली जाएंगी। यह मोदी की गारंटी है।

5 के बाद अंग, बंग और कलिंग में भाजपा का शासन होगा

- अमित शाह ने कहा, एक बहुत बड़ी आशंका बताई जाती थी कि जनसमर्थन तो है, लेकिन वह पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या? अब यह दूर हो गई है। दूसरे चरण के लोगों की जिम्मेदारी है कि बदलाव के दौर का वे आगे बढ़ाएं।
- 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भाजपा का शासन होगा।
- मोदी जी ने 2014 में कहा था भारत माता की दोनों भुजाओं को सम विकास होना चाहिए। पूर्व के क्षेत्र किसी न किसी कारण से पिछड़े हैं।
- भाजपा के शासन के आने बाद जो पूर्वोदय की यात्रा मोदी जी ने शुरू की है वह आगे बढ़ेगीमुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं भाजपा का शासन आया तो बंगाल के लोग बाहर कर दिए जाएंगे।
- मैं दीदी को बताना चाहूंगा कि अगला सीएम बंगाल का ही होगा। वह सिर्फ आपका भतीजा नहीं होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा।

पीएम ने कहा- TMC का दीया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा

मोदी ने बंगाल के दमदम में चुनावी रैली में कहा कि लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण की मतदान ने उस पर मुहर लगा दी। टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था। जनता ने बंगाल के पहले चरण में लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। नतीजों के बाद टीएमसी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी।

बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड 93% मतदान

2 भाजपा कैंडिडेट पर हमला, पथराव, लाठीचार्ज और बम फेंका गया; तमिलनाडु में पहली बार 85% वोटिंग

कोलकाता/चेन्नई (राजधानी चौपाल) | पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बंगाल की 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.72% मतदान हुआ। दो भाजपा कैंडिडेट पर हमला हुआ। एक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। वहीं, मुर्शिदाबाद के नौदा में बुधवार देर रात देसी बम से हमले में कई लोग घायल हो गए। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 85.14% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों में आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान 2011 में 78.29% था, जबकि बंगाल में 2011 में 84.72% मतदान दर्ज किया गया था। ममता ने वोटिंग के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने SIR के खिलाफ बंपर वोटिंग की है।

बंगाल में वोट प्रतिशत बढ़ने की वजह

- SIR: राज्य में 91 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाता संख्या घट गई है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं 152 सीटों पर वोटिंग करीब 80% और 2021 विधानसभा चुनाव में करीब 82.17% रही थी। यानी कुल मतदाता घटे, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या लगभग बराबर या ज्यादा रही।
- **एंटी इनकंबेंसी**: राज्य में 15 साल से तृणमूल सरकार है। नेताओं से असंतोष, रोजगार, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट जैसे मुद्दे भी ज्यादा मतदान की वजह हो सकते हैं। वहीं, मुस्लिम बहुल जिलों और सीमावर्ती इलाकों में यह SIR और NRC के डर से उपजी प्रतिक्रिया भी मानी जा रही है। इस बार ध्रुवीकरण भी जबरदस्त है। इसलिए माना जा रहा है कि हिंदू मतदाताओं का भी वोट प्रतिशत ज्यादा रहा होगा।
- **प्रवासी कामगार**: यह भी बड़ा 'टर्निंग पॉइंट' है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से केवल वोट डालने बंगाल लौटे हैं। उन्हें लगा कि इस बार वोट नहीं दिया, तो हमेशा के लिए अधिकार छिन सकता है। TMC ने आरोप लगाया कि भाजपा ट्रेन भर कर वोट डालने के लिए लोगों को ला रही है।
- **आयोग की सख्ती**: निर्वाचन आयोग की अभूतपूर्व निगरानी और 2.40 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण मतदाताओं ने बिना किसी डर के मतदान किया।

14 साल में पांचवीं बार गेहूं का बंपर उत्पादन

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | मंडियों में गेहूं की बंपर आवक जारी है। यह पिछले 14 साल में पांचवीं बार है, जब इतना गेहूं मंडियों में पहुंचा है। अब तक मंडियों में 77.45 लाख टन से ज्यादा गेहूं की आवक हो चुकी है। अगले दो दिन में इसके 80 लाख टन के पार जाने के आसार बन गए हैं। सिरसा में सबसे अधिक 9.56 लाख टन, जींद में 8.44, करनाल में 7.49 लाख टन, फतेहाबाद में 6.84 लाख टन, कैथल में 6.76 लाख टन, सोनीपत में 4.59, हिसार में 6.44 लाख टन गेहूं की आवक हो चुकी है। सिरसा के गुड़िया खेड़ा में खरीद केंद्र में गेहूं के ढेर लगे हैं।

ट्रम्प के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन

1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी, पार्टी के 10 सांसद विरोध में

वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल)| अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार, किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहां भी ट्रम्प ने खेल किया। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा, संसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रम्प के 53 सांसद हैं। जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 हैं।

ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं। जबकि विपक्षी डेमोक्रेट एकजुट रहने वाले हैं। ऐसे में अब ट्रम्प 1 मई से पहले किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस कानून में 60 दिन के बाद एक विकल्प और है। राष्ट्रपति एक बार के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय ले सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए होता है, न कि युद्ध जारी रखने के लिए।

क्या ट्रम्प 60 दिन की सीमा तोड़ सकते हैं

एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रम्प इस समय सीमा को नजरअंदाज कर सकते हैं। अमेरिका के कई राष्ट्रपति पहले भी यह दलील देते रहे हैं कि संविधान उन्हें सेना के प्रमुख के रूप में कई बड़े अधिकार देता है, इसलिए इस तरह की कानूनी सीमाएं पूरी तरह लागू नहीं होतीं। उदाहरण के तौर पर 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और कहा था कि यह कानून लागू नहीं होता क्योंकि वहां 'लगातार लड़ाई' जैसी स्थिति नहीं थी।

ट्रम्प ने भी अपने पहले कार्यकाल में 2019 में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसमें यमन युद्ध में अमेरिका की भूमिका खत्म करने की बात थी। उन्होंने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश बताया था। लेकिन अगर इस बार ट्रम्प 60 दिन की समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं, तो यह रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक रूप से मुश्किल पैदा कर सकता है।

कुछ बड़े अपडेट्स...

- **इजराइल-लेबनान सीजफायर बढ़ा:** डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में इजराइल और लेबनान के राजदूत स्तर की दूसरी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर को तीन हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया।
- **भारत की एडवाइजरी:** भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को वहां जाने से बचना चाहिए।
- **होर्मुज में टोल वसूली:** ईरान ने गुरुवार को पहली बार होर्मुज में जहाजों से टोल वसूला है। इसे बैंक में जमा भी करा दिया गया है। हालांकि, राशि का खुलासा नहीं किया है।
- **निर्वासित क्राउन प्रिंस का विरोध:** ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी पर बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते वक्त लाल रंग फेंका गया।
- **ट्रम्प की ताकत घटाने में विपक्ष फेल** : अमेरिकी सीनेट में ट्रम्प की युद्ध करने की ताकत को कम करने का प्रस्ताव पांचवीं बार खारिज हो गया। इसके खिलाफ 51 वोट पड़े, जबकि समर्थन में 46 वोट मिले।

कच्चे तेल की कीमतें तीसरे दिन 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार तीसरे दिन 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को 1.8% बढ़कर 101.2 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार और गुरुवार को भी यह 100 डॉलर के ऊपर बंद हुआ था। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क WTI भी 1.8% चढ़कर 97.6 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा।

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष खत्म करने की दिशा में अभी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इजराइल-लेबनान युद्धविराम जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव बना हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की जब्ती और समुद्री सुरक्षा पर सवालों ने भी तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तेल कीमतों में तेजी के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख देखा गया। जापान और हांगकांग के बाजार बढ़त में रहे, जबकि यूरोपीय बाजारों में कमजोरी रही। यदि कच्चा तेल लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर बना रहता है, तो भारत जैसे आयातक देशों पर महंगाई और व्यापार घाटे का दबाव बढ़ सकता है।

22 माह में 7 सांसदों ने 510 सवाल किए; सांसद धर्मबीर सबसे आगे, सैलजा ने सबसे कम सवाल पूछे

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों में भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह सरकार से सवाल पूछने में सबसे आगे हैं। लगभग 22 माह के कार्यकाल में उन्होंने राज्य के सभी सांसदों को सवालों के मामले में पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक 157 सवाल लगाए हैं। राज्य के सात सांसदों की तरफ से इस दौरान कुल 510 सवाल लगाए गए हैं। जिसमें सबसे कम सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के महज 33 ही सवाल हैं। चूंकि राज्य से प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सांसद केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए वह सवाल नहीं लगा सकते हैं।

▪ सक्रिय दिखे राज्य के प्रतिनिधि : 18वीं लोकसभा के जून 2024 में गठन के बाद से अब तक का समय काफी चर्चाओं भरा रहा है। राज्य के सांसदों ने न केवल तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे, बल्कि शून्यकाल के दौरान स्थानीय मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाया। हालांकि इसमें सत्ता पक्ष के सांसदों की भागीदारी अधिक है।

लोकसभा सत्र के दौरान राज्य के इन सात सांसदों ने सदन में अपनी सक्रियता दिखाते हुए प्रदेश व देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सांसद चौ. धर्मबीर सिंह ने पिछले लोकसभा सत्र तक कुल 157 सवाल लगाए हैं, जिनमें उर्वरक की कमी, दूरसंचार व्यवस्था, जिला महेंद्रगढ़ में आधारभूत ढांचे के साथ अन्य जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाया है। दूसरे नंबर पर सवाल करने वालों में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल हैं। जिन्होंने पिछले सत्र तक 105 सवाल पूछे हैं। इसके अलावा रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 70 और हिसार सांसद जयप्रकाश 42 सवाल सरकार से पूछे हैं। इनके अलावा सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने भी 50 सवाल संसद में सरकार से किए। अम्बाला के सांसद वरुण चौधरी ने 53 सवाल किए हैं, जबकि सवाल पूछने के सबसे निचले पायदान पर सिरसा सांसद कुमारी सैलजा हैं। जिन्होंने पिछले सत्र तक 33 सवाल किए। करनाल, गुरुग्राम व फरीदाबाद के सांसद मंत्री होने के कारण उनके द्वारा सवाल नहीं लगाए जा सकते हैं।

जाली दस्तावेजों से रचा पूरा खेल, फर्जी प्रोजेक्ट दिखाकर करोड़ों ठगे

अपर्णा आश्रम की जमीन के नाम पर 4.50 करोड़ ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम में सिलोखरा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरू धीरेंद्र ब्रह्मचारी के 'अपर्णा आश्रम' की जमीन और बाबा के नाम का सहारा लेकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने निवेशकों को फर्जी रियल एस्टेट परियोजनाओं का झांसा दिया और जाली दस्तावेजों के आधार पर करीब 4.50 करोड़ रुपए का निवेश कराया था। आरोपियों की पहचान अशोक चौधरी (60 वर्ष) निवासी गौतम नगर, दिल्ली व चंद्रकांत चौधरी (40 वर्ष) निवासी बृज विहार जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। आर्थिक अपराध शाखा-2 ने इन्हें नोएडा से अरेस्ट किया है।

दरअसल, सेक्टर-40 थाना पुलिस में 15 अप्रैल को एक शिकायत दी गई। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि सीकेसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अशोक चौधरी, चंद्रकांत चौधरी और इनके अन्य साथियों ने अपर्णा आश्रम सिलोखरा, गुरुग्राम और वैशाली में कथित रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर उसे झांसा दिया। आरोपियों ने झूठे दस्तावेज और सेलिंग राइट्स के फर्जी आश्वासन देकर शिकायतकर्ता से अलग-अलग समय पर करोड़ों रुपये का निवेश कराया। भुगतान के बावजूद न तो कोई वैध एग्रीमेंट किया गया, न परियोजना पर काम शुरू हुआ और न ही सेलिंग राइट्स दिए गए। बाद में पता चला कि संबंधित भूमि विवादित है और सरकारी कब्जे में है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच अपराध शाखा-1, को सौंपी गई। जिसके बाद क्राइम ब्रांच-1 ने दोनों आरोपियों को सेक्टर-62, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी सीकेसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी परियोजनाओं के नाम पर शिकायतकर्ता से अपर्णा आश्रम की जमीन पर परियोजना के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए और वैशाली (नोएडा) स्थित परियोजना में निवेश के नाम पर लगभग 4.50 करोड़ रुपए लिए। इसमें से करीब 1 करोड़ रुपए सीकेसी इंफ्रा के बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए। जिसे बाद में आरोपियों ने आपस में बांट लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है।

सरकार ने एक साल पहले अपने कब्जे में ली थी जमीन

हरियाणा सरकार दिवंगत योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी के गुरुग्राम स्थित अपर्णा आश्रम का प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। इससे संबंधित बिल को विधेयक के रूप में 28 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में विधेयक के रूप में मंजूरी दी थी। ब्रह्मचारी ने केंद्र सरकार से समय-समय पर प्राप्त दान की मदद से अपर्णा आश्रम के नाम पर गुरुग्राम की राजस्व सम्पदा में 24 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी थी। संस्था गुरुग्राम के सेक्टर-30 के पास स्थित है।

साइबर ठगी के मामलों में 20 दिन में 135 आरोपी गिरफ्तार किए गए

गुरुग्राम| गुरुग्राम साइबर क्राइम थाना पुलिस साइबर ठगों से सख्ती से निपट रही है। एक अप्रैल से 20 अप्रैल तक साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 135 साइबर ठगों को काबू किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1.93 लाख रुपए की नकदी व 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे साइबर ठगी के अलग-अलग तरीके अपनाते थे। इन तरीकों में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, चालान से संबंधित फ्रॉड, लोन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, साइबर स्लेवरी, फेसबुक पर ऐड डाल कर ठगी व क्रेडिट कार्ड से संबंधित फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.93 लाख रुपए की नकदी बरामद की है।

बिजली लाइनों में फॉल्ट पर तुरंत सूचना देने के निर्देश

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| बिजली निगमों के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने डीएचबीवीएन, यूएचबीवीएन एवं एचवीपीएन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 33 केवी, 66केवी, 132 केवी अथवा 220 केवी की किसी भी विद्युत लाइन या सब-स्टेशन में फॉल्ट आने की स्थिति में, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित होती है, उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूचना के साथ फॉल्ट के कारणों का संक्षिप्त विवरण तथा समस्या के समाधान के लिए अनुमानित समय भी अनिवार्य रूप से बताया जाए, ताकि उच्च स्तर पर स्थिति की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके। निगम प्रवक्ता संजय ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं की त्वरित निगरानी करना तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।

सेक्टर-78,79 में वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए गठित की कमेटी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मानेसर निगम क्षेत्र के सेक्टर- 78,79, गांव नौरंगपुर के लोगों को वायु प्रदूषण के मुक्ति दिलाने की पहल की गई है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह की ओर से एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी के सदस्यों ने मौका निरीक्षण किया। कमेटी एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सादगी... न्यायाधीश प्रियंका वर्मा ने बिना दहेज व डीजे के लिए सात फेरे

फरीदाबाद (राजधानी चौपाल)| उत्तराखंड के त्रियुगीनारायण मंदिर की मान्यता है कि यहां भगवान शिव-पार्वती का विवाह हुआ था। उसी मंदिर में रविवार को एक ऐसा विवाह हुआ जो आज के दिखावटी दौर में मील का पत्थर बन गया। फरीदाबाद में कार्यरत न्यायाधीश प्रियंका वर्मा ने प्रशांत के साथ दहेजमुक्त और सादगीपूर्ण तरीके से वैवाहिक बंधन में बंधकर समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। विवाह में न रात्रि जागरण था, न डीजे की कानफोड़ आवाज, न आतिशबाजी का धुआं और न ही लाखों का लेनदेन । केवल वैदिक मंत्र, अग्नि के फेरे और सीमित परिजनों की मौजूदगी में यह जोड़ा परिणय बंधन में बंधा।

प्रियंका वर्मा के पिता डॉ. अशोक कुमार वर्मा हरियाणा पुलिस में उपनिरीक्षक हैं। वह राष्ट्रपति पुलिस पदक से विभूषित, राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता डायमंड रक्तदाता और पर्यावरण प्रहरी के रूप में पहचाने जाने वाले डॉ. वर्मा दहेज प्रथा के कट्टर विरोधी हैं। प्रियंका की मां सुषमा वर्मा कुरुक्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी हैं। डॉ. वर्मा के अनुसार दहेज जैसी कुरीतियां समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक हैं। उन्होंने हमेशा अपनी संतानों को सादगी, ईमानदारी व आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। बेटियों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने पर उन्होंने जोर रहा। डा. वर्मा का समाज को संदेश है कि बेटियों को दहेज नहीं, शिक्षा और संस्कार दो।

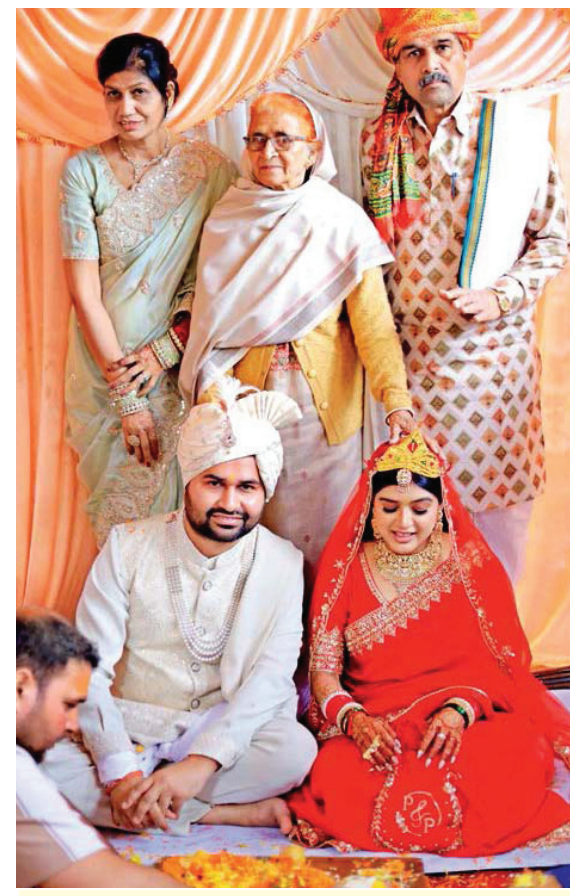

समाज को मिला संदेश... यह विवाह सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आदोलन है। डॉ. वर्मा के अनुसार वह रात्रि विवाह, डीजे, आतिशबाजी व शादियों में होने वाले अनावश्यक खर्च के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाते आ रहे हैं। अव उनकी बेटी ने न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर अपने विवाह से पिता की मुहिम को जमीन पर उतार दिया। इस पहल ने साबित किया कि जब सोच बड़ी हो तो बदलाव धर से हो।

नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का कांग्रेस ने विरोध करके किया अक्षम्य अपराधः सुधांशु

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला शक्ति को समुचित स्थान और यथोचित सम्मान दिया है। लेकिन कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की नारी विरोधी सोच के चलते नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पास नहीं हो पाया। विपक्ष ने तालियां बजाकर, मेजें थपथपाकर, हंसी उड़ाकर महिला शक्ति का अपमान किया।

शुक्रवार को गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय गुरुकमल में प्रेसवार्ता में सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण नीतियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को विपक्ष की नकारात्मक सोच के कारण पारित नहीं किया जा सका। संसद में विपक्षी नेताओं का व्यवहार महिलाओं के सम्मान के खिलाफ था। "सदन में जिस प्रकार से हंसी, ताली और उपहास किया गया वह नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व विपक्षी पार्टियों का यह आचरण देश की महिलाओं के हृदय में एक शूल की तरह चुभ गया है, जिसका उचित समय आने पर विपक्ष को उचित जवाब महिला शक्ति देने का काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष समाज को बांटने की राजनीति कर रहा है और उत्तर-दक्षिण के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहा है जोकि देशहित के खिलाफ है। त्रिवेदी ने कहा कि महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में जाने का अच्छा अवसर था, लेकिन विपक्ष ने रोड़ा अटकाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी अवसर चूका है, लेकिन अंतिम निर्णय बाकी है। अब विपक्ष कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है।

कमेटी में शिकायतों के बाद भी 'निरोग' नहीं हो पा रहा कॉलेज

राव नरबीर के सामने रखी बदहाली की शिकायत

नूंह (राजधानी चौपाल)| ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लगातार शिकायतें रखे जाने के बाद भी शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। प्रबंधन की स्थिति ऐसी है कि बैठक में निवारण का वादा तो करते हैं लेकिन जमीनी सच्चाई अगली बैठक में फिर सामने आ जाती है। उद्योग मंत्री राव नरबीर ने मेडिकल कॉलेज के निदेशक को इलाज संबंधी सुविधाएं और रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार को आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आसिफ अली ने मेडिकल कॉलेज की बदहाली की शिकायत रखी। इस पर ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन व सूबे के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निदेशक को निर्देश दिए कि मरीजों के लिए इलाज संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। रेडियोलॉजिस्ट व कार्डियोलॉजिस्ट जैसे जो भी पद रिक्त हैं, उन पर नियुक्ति जल्द से जल्द करवाएं तथा मरीजों को निशुल्क दवाइयां व पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाएं। मंत्री ने गांव जटवाड़ा में प्राइमरी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे की जितेंद्र की शिकायत को भी गंभीरता से लिया।

न्यूज ब्रीफ

मकान मालिक को डराने के लिए दुष्कर्म की झूठी सूचना दी, महिला पर केस दर्ज

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| सदर थाना एरिया में दुष्कर्म की झूठी सूचना देने पर पुलिस ने महिला पर केस दर्ज कर लिया है। महिला ने 112 नंबर पर कॉल करके झूठी सूचना देकर पुलिस का समय खराब किया। जानकारी के अनुसार गत 20 अप्रैल 2026 को डायल 112 के माध्यम से सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-47 स्थित एक मकान में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि नेपाल कि वह रहने वाली है और ऑनलाइन कंपनी के लिए खाना बनाने का काम करती है। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि महिला का मकान मालिक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।

तीसरी मंजिल से गिरने से घायल हुई युवती की इलाज के दौरान मौत

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| आईएमटी मानेसर थाना के अंतर्गत 21 अप्रैल को बास कुशला गांव स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हुई युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक युवती की पहचान मथुरा (उत्तर प्रदेश) के पन्ना पुर गांव निवासी सायरा (21 वर्ष) के रूप में हुई है। वह करीब डेढ़ साल से अपनी मौसी की डिलीवरी के चलते बास कुशला गांव में उनके पास आई थी। परिवार मकान की दूसरी मंजिल पर किराए पर रहता है। सायरा तीसरी मंजिल की छत पर कपड़े उतारने के लिए गई थी। इसी दौरान उसका पैर फिसलने से नीचे गिर गई।

3 मई को होगी नीट यूजी परीक्षा, 18 केंद्रों पर 6875 अभ्यर्थी होंगे शामिल

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| डीसी उत्तम सिंह की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आगामी 3 मई 2026 को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 के सफल, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा बैठक की गई। बैठक में परीक्षा केंद्रों की तैयारी, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग व्यवस्था, पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती और संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। देशभर में लगभग 22 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।

नकली इंजेक्शन मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपी भेजा जेल

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम में मौनजारों के नकली इंजेक्शन रैकेट मामले में शुक्रवार को एक और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पांच दिन की पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद जांच एजेंसियों ने कोर्ट के सामने अब तक की जांच रिपोर्ट पेश की। ज्ञात हो कि गत शनिवार को टीम ने डीएलएफ फेज-4 में एक गाड़ी से 70 लाख रुपए के इंजेक्शन बरामद किए थे। इसी मामले में जांच करते हुए टीम सोमवार को सेक्टर-62 की सोसाइटी में फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। टीम ने मौके से पैकेजिंग मशीनें भी बरामद की थी।

पंचग्राम प्राधिकरण के तहत पांच नए शहर बसाए जाएंगे

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को लेकर एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। उन्होंने कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पांच नए शहर विकसित किए जाएंगे। इन शहरों के सुनियोजित विकास के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि इन शहरों का ढांचा सिंगापुर जैसे आधुनिक वैश्विक केंद्रों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यह क्षेत्र आधुनिक शहरीकरण और औद्योगिक प्रगति का एक बेजोड़ उदाहरण बनेगा। प्रदेश में निवेश और रोजगार को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2030 तक दस नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दस में से पांच आईएमटी को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है और उन पर विकास कार्य तेजी से जारी है। प्रस्तावित 10 आईएमटी में से तीन विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विकसित की जाएंगी।

मौसम का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार,लू का येलो अलर्ट जारी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| जिले में शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। जिले में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,जो सामान्य 4.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया,जो सामान्य चार डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। दिनभर चली गर्म हवाओं(लू) ने राहगीरों और कामकाजी लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। शुक्रवार सुबह की शुरुआत ही उमस और तपन के साथ हुई। आमतौर पर सुबह के समय मौसम सुहावना रहता है।

एचएसवीपी की पांच टीम 27 अप्रैल से आठ मई तक तोड़फोड़ करेंगी

सख्ती : 51 सेक्टरों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मिलेनियम सिटी के 51 सेक्टरों में अवैध निर्माण पर सोमवार से बुलडोजर चलेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से यह कार्रवाई की जाएगी। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी एक और दो ने सेक्टर-तीन से लेकर सेक्टर-57 तक विकसित 49 सेक्टरों के अलावा सेक्टर-37सी और सेक्टर-110ए के निवासियों से आग्रह किया है कि वह खुद अतिक्रमण हटा लें। शुक्रवार को एचएसवीपी की संपदा अधिकारी डॉ. अनुपमा मलिक ने सेक्टर-34 स्थित अपने कार्यालय में एक वार्ता को संबोधित किया।

उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से लेकर आठ मई तक तोड़फोड़ की जाएगी। इसको लेकर पांच टीम का गठन किया है, जो अलग-अलग सेक्टरों में तोड़फोड़ करेंगी। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को सेक्टर-24, 25ए, 27, 43, 31-32ए और 30 में तोड़फोड़ होगी।

मकानों की सूची बनेगी

संपदा अधिकारी-एक राकेश सैनी और संपदा अधिकारी-दो डॉ. अनुपमा मलिक ने बताया कि तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान कब्जा प्रमाण पत्र का उल्लंघन कर रहे मकानों की सूची बनेगी। स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से कमरों का निर्माण लोगों ने कर लिया है। कारों को घर के बाहर खड़ा किया जाता है। घरों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में इन मकानों के खिलाफ एचएसवीपी की विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मलबा उठान को लेकर तकरार : डीटीपीई अमित मधोलिया ने पांच दिन तक तोड़फोड़ अभियान चलाकर करीब साढ़े सात हजार मकानों के सामने से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़ा है। मधोलिया ने गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया से आग्रह किया था कि तोड़फोड़ के बाद सड़कों पर फैले मलबे का उठान कराएं।

29 अप्रैल और 30 अप्रैल को सेक्टर-39, 45, 28, 42 और 51 में बुलडोजर चलेगा। डॉ. मलिक के मुताबिक चार मई और पांच मई को सेक्टर-57, 49, 50, 38, 46, 40 और 41 में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर-52, 47, 55, 56, 52ए और 53 में छह मई और सात मई को बुलडोजर चलेगा। आठ मई को सेक्टर-54, 29, 32 और सेक्टर-44 में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस दौरान सड़कों पर अवैध रूप बनाए गए किचन गार्डन, निजी पार्क, गमलों, मकानों के ऊंचे रैंप, रेहड़ियों, क्योसक के अलावा अन्य अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई 29 सेक्टरों में होगी। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी-एक राकेश सैनी ने बताया कि उनके कार्यालय अधीन आ रहे 22 सेक्टरों में सोमवार से बुलडोजर चलाया जाएगा। यह कार्रवाई एक जुलाई तक चलेगी।

सोमवार को सेक्टर-21 से कार्रवाई की शुरूआत की जाएगी। 28 अप्रैल को भी इस सेक्टर में अभियान चलाया जाएगा। 30 अप्रैल और एक मई को सेक्टर-चार, चार मई को सेक्टर-पांच, छह मई को सेक्टर-तीन, आठ मई को सेक्टर-छह, 11 मई और 14 मई को सेक्टर-सात, 15 और 18 मई को सेक्टर-सात एक्सटेंशन, 19 और 20 मई को सेक्टर-नौ, 21 और 22 मई को सेक्टर-नौए, 25 मई और 26 मई को सेक्टर-10, 28 मई और 29 मई को सेक्टर-10ए, एक जून और दो जून को सेक्टर-12ए, तीन जून और चार जून को सेक्टर-14, पांच जून और आठ जून को सेक्टर-15 के पार्ट एक, नौ जून और 10 जून को सेक्टर-15 के पार्ट दो समेत कई स्थानों पर तोड़फोड़ होगी।

महिलाओं के लिए हॉस्टल दो वर्ष में बनकर तैयार होगा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| सेक्टर-9 में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल दो वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से टेंडर आवंटित होने के बाद ठेकेदार कंपनी ने परियोजना स्थल पर खुदाई का काम शुरू कर दिया है। इस हॉस्टल के बनने के बाद करीब 125 कामकाजी महिलाओं को रहने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एचएसवीपी ने फरवरी इस हॉस्टल को तैयार करने का ठेका एक कंपनी को आवंटित किया है। इसके निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पांच मंजिला इस हॉस्टल में 60 कमरों का निर्माण किया जाएगा। इसमें कैंटीन, लाइब्रेरी और डोरमेट्री की सुविधा होगी। स्टिल्ट पार्किंग में करीब 53 कारों को खड़ा करने की व्यवस्था की जाएगी। दुपहिया वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी इस कामकाजी हॉस्टल में होगी।

बता दें कि गुरुग्राम के सिविल लाइंस में फिलहाल एक कामकाजी महिला हॉस्टल है। इसके अधिकांश कमरे हमेशा बुक रहते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं गुरुग्राम में काम करती हैं। सरकारी हॉस्टल की सुविधा न होने से इन्हें मजबूरी में निजी पीजी या गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है।

एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता विमलदीप सिंह ने बताया कि सेक्टर-नौ में अभिनव सोसाइटी के समीप कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दो साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह हॉस्टल ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत बसई तालाब के समीप प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है। हॉस्टल में 125 महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। कार और दुपहिया वाहनों की पार्किंग का पर्याप्त बंदोबस्त किया जाएगा।

मैट्रो स्टेशन के समीप हॉस्टल : करीब एक एकड़ जमीन पर यह हॉस्टल सेक्टर-नौ में अभिनव सोसाइटी से बिल्कुल सटकर तैयार हो रहा है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत बसई तालाब के समीप मेट्रो स्टेशन तैयार होना है। हॉस्टल साइट इस प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से करीब आधा किमी की दूरी पर स्थित है। जब तक यह हॉस्टल बनकर तैयार होगा, तब तक ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के तहत अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

श्रमिकों के मुद्दों पर और बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगेगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को गुरुग्राम में कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह नौ बजे होगी। इसमें प्रदेश की आर्थिक राजधानी और एनसीआर क्षेत्रों के विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगने की उम्मीद है।

बैठक में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में शहरी विकास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा हाल ही में मानेसर में हुए औद्योगिक विवादों को देखते हुए वेतन और श्रमिक मुद्दों पर भी फैसला लिया जा सकता है। यह कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ से बाहर गुरुग्राम में पहली बाहर आयोजित हो रही है, जो शहर के बढ़ते प्रशासनिक और आर्थिक महत्व को दर्शाता है।

इस बैठक में राज्य भर में विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्री अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, श्रुति चौधरी और विपुल गोयल शिरकत करेंगे। कैबिनेट में जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब 12 अहम एजेंडों पर चर्चा होगी। बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसी उत्तम सिंह ने बैठक की तैयारियों को लेकर मंगलवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए।

दुष्यंत चौटाला के बाद जेजेपी नेता सीआईए के हुए खिलाफ

हिसार के 3 अलग-अलग थानों में शिकायत, घर में घुसकर डीवीआर चुराने के लगाए आरोप

हिसार (राजधानी चौपाल) | हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के बाद जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के छह नेताओं की गिरफ्तारी का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। जमानत पर बाहर आए तीन नेताओं ने भी CIA के खिलाफ अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई है। इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मचारी सिविल ड्रेस में उनके घर में जबरन घुसे, हथियार दिखाकर डराया और डीवीआर चोरी कर ले गए। यह कार्रवाई गैर कानूनी है। पुलिस के पास कोई वारंट नहीं था। इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

इन्हीं नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 17 अप्रैल को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार में गिरफ्तारी देने जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईए इंचार्ज ने काफिला रोककर वैपन दिखाया और कुचलने की कोशिश की। दुष्यंत भी सीआईए इंचार्ज के खिलाफ शिकायत दे चुके हैं। वहीं सीआईएइंचार्ज ने भी दुष्यंत के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस प्रवक्ता मदनलाल ने बताया कि जजपा नेताओं की तरफ से शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट में दुष्यंत चौटाला की याचिका मंजूर

सब्जी मंडी पुल पर CIA इंचार्ज पवन कुमार से हुए विवाद के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने हिसार एसपी को एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। दुष्यंत चौटाला ने 23 अप्रैल को याचिका दायर की थी। इसमें हिसार पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने समेत कई आरोप लगाए। दुष्यंत का कहना है कि वह एसपी को चार बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। उनका यह भी आरोप है कि पूरे घटनाक्रम में डीएसपी खुद दोषी हैं, फिर भी जांच उन्हीं को सौंपी गई है।

जानिए किस नेता ने कौन से थाने में शिकायत दी...

- **बिजेंद्र धानक, प्रधान, एससी सेल:** बिजेंद्र धानक ने अग्रोहा थाने में पॉक्सो एक्ट, DVR चोरी और धमकाने की शिकायत दी है। उनका आरोप है कि जब पुलिस टीम उनके घर पहुंची, तो साथ में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। उनकी नाबालिग बेटी कमरे में सो रही थी। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी उसके पैरों पर पैर रखकर DVR ले गया।
- **जितेंद्र श्योराण, पूर्व प्रत्याशी:** जितेंद्र श्योराण ने अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मी के उनके घर में घुस गई। उनकी पत्नी के कपड़े अलमारी से निकाल दिए और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की DVR उखाड़ ली। 2-3 दिन बाद सादे कपड़ों में कुछ लोग आकर DVR वापस दे गए। उन्हें आशंका है कि डेटा से छेड़छाड़ की गई है, इसलिए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- **गौरव सैनी, युवा हलका अध्यक्ष:** गौरव सैनी ने शुक्रवार शाम हिसार की पुरानी सब्जी मंडी चौकी में शिकायत दी। उनका आरोप है कि सादे कपड़ों में कुछ लोग आधी रात को हथियार लेकर उनके घर में घुस गए और नाबालिग बेटे के सामने बंदूक तान दी, जिससे उनका परिवार डर गया। जाते समय वे लोग DVR उखाड़कर ले गए।

दुष्यंत चौटाला: सीआईए इंचार्ज विवाद में पुलिस ने सीसीटीवी जारी की

हिसार में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के मामले में हिसार पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी की है। इस फुटेज में दुष्यंत चौटाला के काफिले में शामिल पायलट गाड़ी, पुलिस की बोलेरो गाड़ी को ओवरटेक करते हुए दिख रही है। डीएसपी कमलजीत ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पायलट गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई। दुष्यंत चौटाला को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और उन्हें

डीएसपी बोले : पायलट रखने की मंजूरी नहीं, गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की

पायलट गाड़ी रखने की मंजूरी नहीं है। वह प्राइवेट गाड़ी को पायलट गाड़ी के तौर पर चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज की शिकायत मिली है, जिसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है, जिसमें निजी पायलट गाड़ी का कोई प्रावधान नहीं है : डीएसपी कमलजीत

- **16 अप्रैल को जीजेयू में प्रदर्शन किया :** डीएसपी कमलजीत ने बताया कि 16 अप्रैल

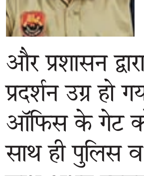

को जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला अपने समर्थकों के साथ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी (जीजेयू) में वीसी ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। पुलिस और प्रशासन द्वारा समझाने के बावजूद प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के गेट को तोड़ने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस व यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार किया।
- **गिरफ्तारी देने जा रहे थे दुष्यंत-दिग्विजय :** डीएसपी ने आगे बताया कि यूनिवर्सिटी के प्रोटेक्टर अनिल कुमार की शिकायत पर सिटी थाना में दिग्विजय समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। 17 अप्रैल को इनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। 17 अप्रैल को ही सूचना मिली कि दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला अपने समर्थकों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने सिटी थाना पहुंच रहे हैं। सीआईए टीम सुरक्षा के मद्देनजर सिविल ड्रेस में पहले ही रवाना हो गई।
- **पायलट गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश :** डीएसपी ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला के काफिले में शामिल एक निजी पायलट गाड़ी तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी। पायल गाड़ी से कई बार पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की गई और टक्कर मारने की कोशिश की। सब्जी मंडी पुल के पास CIA इंचार्ज ने गाड़ी रोककर ड्राइवर को चेतावनी दी। इसी दौरान दिग्विजय चौटाला ने एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता की।
- **निजी पायरल रखने का प्रावधान नहीं :** डीएसपी कमलजीत ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को "वाई प्लस" सिक्योरिटी मिली है, जिसमें निजी पायलट गाड़ी का कोई प्रावधान नहीं है। वह प्राइवेट गाड़ी को पायलट गाड़ी के तौर पर यूज कर रहे थे। यह वाई प्लस के नियमों की अवहेलना है। पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें मिली हैं। निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मैं इसका इंचार्ज हूं।

पुलिसकर्मी के हाथों में एके-47 थी : दुष्यंत चौटाला

- **पुलिसकर्मी के हाथों में एक-47 थी :** 18 अप्रैल को चंडीगढ़ में दुष्यंत चौटाला ने प्रेस

कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि 17 अप्रैल को जब वे गिरफ्तारी देने जा रहे थे तो सब्जी मंडी पुल पर उनके पीछे एक फर्जी नंबर की बोलेरो गाड़ी आई, जिसे डेढ़ साल पहले खरीदा गया था। काफिले के आगे गाड़ी अड़ा दी। उसमें से इंस्पेक्टर पवन उतरा, उसके हाथ में हथियार था। उस गाड़ी में पांच लोग थे, जिनमें एसपी सिक्योरिटी इंचार्ज अमरजीत भी था। पुलिसकर्मी अनिल के हाथों में एके-47 थी।
- **पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाई :** दुष्यंत ने आगे कहा कि पुलिस ने अपनी गलती छिपाने के लिए उन पुलिसकर्मियों को ऑफ ड्यूटी दिखाया। मिल गेट सीआईए इंचार्ज पवन कुमार दो किमी दूर सब्जी मंडी पुल पर हमारी गाड़ी के आगे क्यों आया। उसके पास सरकारी गाड़ी कैसे थी। सभी के हाथ में हथियार थे। पुलिसकर्मियों ने सब्जी मंडी पुल पर सीसीटीवी डिलिट करवाए। वह चाहते हैं उनकी गलती पकड़ में न आए। हम कोर्ट में जाकर सभी फुटेज को सुरक्षित रखवाएंगे।

बेतुके नोटिस जारी कर आमजन को परेशान कर रहा है विभाग : जितेंद्र श्योराण

हिसार (राजधानी चौपाल) | सैक्टर 16-17 एवं 9-11 के पूर्व प्रधान जितेंद्र श्योराण ने एचएसवीपी की उस कार्यवाही पर रोष जताया है जिसमें विभाग द्वारा सैक्टर्स में लोगों के घरों के सामने बनाई गई ग्रीन बेल्ट को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और आगामी 28 अप्रैल से ग्रीन बेल्ट हटाने की कार्यवाही शुरू करने की बात कही गई है। जितेंद्र श्योराण ने इसे विभाग का तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि एचएसवीपी विभाग खुद तो सैक्टर्स को सुंदर बनाने और लोगों को सुविधाएं में नाकायाब रहा है लेकिन अब सैक्टरवासियों द्वारा अपने घरों के सामने जो ग्रीन बेल्ट विकसित कर सैक्टर को सुंदर व हरा-भरा बनाने में योगदान दिया गया है उसे विभाग तोडऩे की बात कहकर कुचलने का काम रहा है। यह विभाग का सरासर तानाशाही और बेतुका फरमान है जिसने सैक्टरवासियों को परेशानी में डाल दिया है क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत से पौधे लगाकर अपने घरों के सामने ग्रीन एरिया विकसित किया था उन्हें तोडक़र विभाग सैक्टर में हरियाली की उम्मीदों पर भी पानी फेरने का काम कर रहा है।

प्रमुख समाजसेवी स्व. बी.के. भारती की पुण्य तिथि पर हवन कर श्रद्धांजलि दी

हिसार (राजधानी चौपाल) | दास संस्था द्वारा संचलित भारती सेवा सदन धर्मशाला, बारह क्वार्टर रोड हरि नगर में संस्था के संस्थापक स्व. बी.के.भारती की पांचवीं पुण्य तिथि पर हवन किया गया। संस्था के प्रधान जितेन्द्र भारती ने बताया कि परिवार के सदस्यों के अलावा नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने स्व. बी.के.भारती के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने हवन में आहुति डाली। वक्ताओं ने सेवानिवृत प्रधानाचार्य स्व. बी.के.भारती द्वारा समाज को दिये गये योगदान को याद किया गया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया हुआ था। हर किसी के सुख-दुख में शामिल होकर अपना आशीर्वाद देते थे। इस अवसर पर संस्था के प्रधान जितेन्द्र भारती, ऊषा किरण भारती आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

न्यूज ब्रीफ

जीवन को सुधारने और आत्मा को जागृत करने का सबसे सशक्त माध्यम है सत्संग : रामचरण गुप्ता

हिसार (राजधानी चौपाल) | तरसेम नगर स्थित बाबा बालक नाथ एवं दुर्गा माता मंदिर में जेठा रविवार के पावन अवसर पर भव्य सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर जय बाबा बालक नाथ के जयकारों से गूंजा उठा। सत्संग के दौरान श्रद्धालु बाबा बालक नाथ जी के भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य सेवक रामचरण गुप्ता ने कहा कि सत्संग केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने और आत्मा को जागृत करने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि सत्संग में बैठने मात्र से व्यक्ति के विचारों में शुद्धता आती है और उसका जीवन स्वतः ही सद्मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। रामचरण गुप्ता ने कहा कि आज हम भौतिक सुखों की दौड़ में अपनी आध्यात्मिक जड़ों को भूलते जा रहे हैं लेकिन सत्संग हमें वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। उन्होंने कहा कि प्रभु का सिमरन मन की अशांति को दूर कर आत्मिक शांति प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। उन्होंने कहा कि सत्संग हमें यह सिखाता है कि जीवन में सेवा, त्याग, प्रेम और सहनशीलता का कितना महत्व है। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है और सत्संग के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन की हर बाधा स्वतः ही दूर होने लगती है। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

रिटायर्ड कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा

हिसार (राजधानी चौपाल) | अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्ज फैडरेशन के आह्वान पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर तथा राज्य व केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में आज जिला उपायुक्त कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल जाखड़ ने की व संचालन जिला सचिव नरेश कुमार गौतम ने किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य उपप्रधान निर्मला देवी ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार पूर्व में प्राप्त उनके अधिकारों को एक-एक करके समाप्त कर रही है। कभी आठवें वेतन आयोग के लाभ को रिटायर कर्मचारियों पर लागू न करना तो कभी पुरानी पेंशन स्कीम समाप्त करके यूनाइटिड पेंशन स्कीम लागू करने का प्रयास व धीरे-धीरे पेंशन से हाथ धोने पर मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एलटीसी को वही पुराने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली स्कीम को लागू करने का आदेश, कोई केशलेस मेडिकल सुविधा नहीं देकर संगठनों को कमजोर करने वाले श्रम कानून लागू कर सरकार कर्मचारियों की एकता को तोड़ना चाहती है। रमेश आहुजा व जगदीश चंद्र बिश्नोई ने कहा कि विधायकों व सांसदों के वेतन व भत्ते हर साल बढ़ा दिये जाते हैं और कर्मचारी 10-10 वर्षों तक इंतजार करते हैं। हिसार के अलावा प्रदेश भर के हर जिले में प्रदर्शन किये गये व उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजे गये। प्रदर्शन को मा. जयबीर सिंह, ओमप्रकाश झाझडिय़ा, नानक देव रानोलिया, श्योचंद राम घोड़ेला, अशोक सैनी, अशोक अठवाल, प्रदीप जांगड़ा, सूबेसिंह, जयसिंह, मा. जसवंत सिंह आदि ने संबोधित किया।

सावित्री मक्खनलाल जनकल्याण ट्रस्ट के चुनाव के लिये आम सभा 3 मई को

हिसार (राजधानी चौपाल) | सावित्री मक्खनलाल जनकल्याण ट्रस्ट की महत्वपूर्ण आम सभा 3 मई को माता सावित्री शक्तिधाम, रिसालूखेड़ा (अग्रोहा) जिला हिसार में आयोजित की जाएगी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का गठन करना तथा सभी सदस्यों एवं समाज के बन्धुओं के सुझाव लेकर आपसी सहमति (आम राय) से निर्णय लेना है। यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संरक्षक वेद प्रकाश सोनी एवं आम राय बनाने हेतु गठित कमेटी के सदस्य एडवोकेट नरेश सोनी तूणगर व कार्यकारिणी के पूर्व प्रधान महेन्द्र सोनी छपरवाल ने बताया कि 3 मई को आयोजित होने वाली आम सभा में सभी उपस्थित जनों के विचार एवं सुझावों को महत्व देते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का प्रयास है कि यह गठन आपसी सहमति से हो ताकि किसी भी प्रकार के वाद-विवाद अथवा मतदान की स्थिति से बचा जा सके और संगठन में एकता एवं सौहार्द बना रहे। ट्रस्ट के संरक्षक वेद प्रकाश सोनी ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों, माता के भक्तों एवं समाज के सम्मानित बन्धुओं से विनम्र अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने बहुमूल्य सुझाव दें तथा इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बनें।

अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने किया पौधारोपण

हिसार (राजधानी चौपाल) | अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा द्वारा न्यू अग्रसेन कॉलोनी

स्थित तिकोना पार्क में पौधारोपण किया गया। इस दौरान परिषद की तरफ से 7 पौधे लगाए गए। शाखा गतिविधि संयोजक पर्यावरण मुरारीलाल सिंगला ने बताया की सेवा, संस्कार, संपर्क, सहयोग व समर्पण के साथ-साथ पर्यावरण प्रकल्प पर भी कार्य करती है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री सिंगला ने बताया की पृथ्वी दिवस के अवसर पर विवेकानंद शाखा ने सात पौधे लगाए जिनमें मोर पंखी, मधुकामनी व रात की रानी मुख्य हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासी व परिषद सदस्य अशोक शर्मा, मनीष जैन व खुशीराम गोयल नियमित रूप से पौधों की देखभाल करेंगे।

इस अवसर पर तिकोना पार्क समिति के प्रधान नरेंद्र बंसल, रामकुमार गोयल व प्रवीण जांगड़ा सहित आरडब्ल्यूए के अनेक सदस्यों ने परिषद के अध्यक्ष राजेश जैन, सचिव सूर्य गोयल, अशोक गर्ग तिलकधारी, संजीव जैन, सुमित मित्तल, नविन जैन, महिला संयोजिका डॉली जैन, रेनू मंगल, रेनू सिंगला, पिंकी गोयल व मधु शर्मा का स्वागत किया। परिषद सदस्यों ने पार्क समिति अध्यक्ष नरेंद्र बंसल का अंग वस्त्र पहना कर स्वागत किया।

उकलाना नगर पालिका चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन

कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, चेयरपर्सन के लिए अभी 2 उम्मीदवार

उकलाना (राजधानी चौपाल) | हिसार जिले की उकलाना नगरपालिका के 10 मई को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है और उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपने पर्चे जमा कर सकते हैं। अंतिम दिन को देखते हुए नगर पालिका कार्यालय में हलचल बढ़ने की संभावना है।

अब तक चेयरपर्सन पद के लिए दो ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें निकिता गोयल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है, जबकि रीमा सोनी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस द्वारा अंतिम दिन अपने प्रत्याशी की घोषणा की जा सकती है। इसको लेकर विधायक नरेश सेलवाल लगातार सक्रिय हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है।

कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रमुख धड़ों कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच संतुलन साधने की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी टिकट किस गुट के खाते में जाता है। दोनों खेमे इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं पार्षद पद के लिए चुनावी तस्वीर काफी दिलचस्प बनती नजर आ रही है। नगरपालिका के 16 वार्डों में अब तक कुल 44 उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। इससे कई वार्डों में सीधा मुकाबला होने की संभावना है।

गुरु द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल में मनाया पृथ्वी दिवस

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल) | गुरु द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल में पृथ्वी दिवस बड़े ही उत्साह, जागरूकता और उमंग के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय परिसर पूरी तरह हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के संदेशों से सराबोर नजर आया। विद्यार्थियों में पृथ्वी के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना जागृत करने के उद्देश्य से अनेक रचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में स्लोगन राइटिंग एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रभावशाली और प्रेरणादायक संदेशों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का महत्व उजागर किया। उनके शब्दों में जागरूकता के साथ-साथ एक सकारात्मक सोच और बदलाव की प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वहीं पोस्टर मेकिंग

प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशक्ति और कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। रंग-बिरंगे पोस्टरों के माध्यम से उन्होंने प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अत्यंत आकर्षक और सजीव रूप में प्रस्तुत किया। हर पोस्टर एक संदेश दे रहा था कि यदि अभी नहीं संभले, तो भविष्य संकट में पड़ सकता है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन के चेयरमैन 'श्री भूपसिंह ज्याणी जी. निदेशक 'श्री अजय ज्याणी' जी तथा प्राचार्या 'डॉ अमिता ग्रेवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्या महोदया ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि पृथ्वी हमारी जीवनदायिनी है और इसकी सुरक्षा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। यदि हम छोटे-छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना अपनाएं, तो हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी प्रेरित किया कि वे केवल एक दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक करें। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर पृथ्वी को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प लिया। यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि विद्यार्थियों के मन में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता और कर्तव्यबोध उत्पन्न करने में अत्यंत सफल सिद्ध हुआ।

विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया पृथ्वी दिवस, विभिन्न गतिविधियों का आयोजन

हिसार (राजधानी चौपाल) | अर्बन एस्टेट, स्थित विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पृथ्वी दिवस बड़े ही उत्साह, जोश और पर्यावरणीय जागरूकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए कई सार्थक आयोजन किए। प्रातःकालीन सभा कक्षा पहली से पाँचवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष प्रार्थना सभा के रूप में आयोजित की गई। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने पृथ्वी संरक्षण पर ओजस्वी भाषण दिए, आकर्षक स्लोगन प्रस्तुत किए तथा 4 आर (रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, रिफ्यूज) साइकल के महत्व को रचनात्मक अंदाज में समझाकर सभी का मन मोह लिया। वहीं, कक्षा छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी गहरी समझ और सृजनात्मक सोच का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पौधारोपण रहा जिसमें विद्यालय के चारों सदनों के स्वयंसेवी छात्रों ने प्रधानाचार्य महोदय तथा विज्ञान विषय की अध्यापिकाओं के साथ मिलकर विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। इस गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भाव विकसित करना था। इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि यह हर दिन प्रकृति के संरक्षण की दिशा में हमारे प्रयासों की याद दिलाता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को निरंतर पर्यावरणीय प्रयासों में सक्रिय भागीदारी देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने यह संकल्प लिया कि वे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल, आदमपुर में पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों का आयोजन

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल) | श्री कृष्ण प्रणामी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में पौधारोपण, सफाई अभियान तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इस विशेष सभा का आयोजन अहिल्या बाई हाउस के सभी सदस्यों के पूर्ण सहयोग से किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री धर्मपाल पनिहार ने अपने प्रेरणादायक शब्दों के

माध्यम से विद्यार्थियों एवं विद्यालय परिवार को पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी दिवस की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। 1969 के कैलिफोर्निया तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय त्रासदियों के बाद, इसे एक राष्ट्रीय प्रदर्शन के रूप में शुरू किया गया, जिसमें लाखों अमेरिकी शामिल हुए। आज यह 193 से अधिक देशों में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन है। विद्यालय के प्रशासक श्री पंकज मक्कड़ ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "हरित बनाएं, भविष्य बचाएं" और सभी को अधिक से अधिक पौधारोपण करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सभी के लिए एक यादगार अनुभव रहा।

हरियाणा में लांच होगा किसान ई-खरीद ऐप: पेमेंट, बुआई, गेट पास सबकी जानकारी होगी

सीएम सैनी बोले- मैं राजा नहीं, किसान का बेटा हूं

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में किसानों को राहत देते हुए घोषणा की कि अगले सीजन से 'किसान ई-खरीद एप' लॉन्च किया जाएगा। जिसमें किसानों को अपने जे फॉर्म, भुगतान का स्टेटस, बुआई, भूमि वेरिफिकेशन, गेट पास आदि की जानकारी दी जाएगी। धान मिलों के भुगतान को भी ई-खरीद प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और तेज हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते से किसानों को व्हाट्सएप से क्यूआर कोड आधारित जे फॉर्म भेजा जाएगा, ताकि किसानों को बैंक ऋण लेने में कोई समस्या न आए।

रबी सीजन में हुई गेहूं की बंपर आवक : सीएम : नायब सिंह सैनी ने गेहूं खरीद, उठान और आवक को लेकर कहा कि रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक दर्ज की गई है। पूरी खरीद व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को समय पर खरीद, उठान और भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं राजा नहीं, किसान का बेटा हूं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और सम्मान के साथ मिले।" पंजाब के विधायकों के भाजपा जॉइन करने के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा वो तो खुद ही अपना पिंड छुड़वाना चाह रहे हैं।

साढ़े 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंचा : मुख्यमंत्री ने बताया कि 24 अप्रैल तक प्रदेश की मंडियों में 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई है, जिसका कुल मूल्य 21 हजार 41 करोड़ रुपए है। वहीं 11 अप्रैल को एक ही दिन में 7 लाख 71 हजार मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड आवक हुई। अब तक 5 लाख 80 हजार किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 79 लाख 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक बेरिफिकेशन हो चुका है, जो कुल आवक का लगभग 97 प्रतिशत है। प्रदेश की मंडियों में 70 लाख 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, जिसमें से 59 लाख 77 हजार मीट्रिक टन की सत्यापित खरीद हो चुकी है। वहीं, मंडियों से 34 लाख 56 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है और इस कार्य में और तेजी लाई जा रही है।

पोर्टल पर 10 लाख रजिस्ट्रेशन : मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 'मेरी फसल- मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर 10 लाख 7 हजार 657 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ई-खरीद पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एजिट पास की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत इस सीजन में अब तक 13 लाख 47 हजार डिजिटल गेट पास जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-फेंसिंग और सीसीटीवी निगरानी जैसे आधुनिक सुधार लागू किए गए हैं।

48 से 72 घंटे के भीतर होगा भुगतान : सीएम ने बताया कि, फसल खरीद के बाद किसानों को 48 से 72 घंटे के भीतर भुगतान उनके खातों में सुनिश्चित किया जा रहा है। दूर-दराज से आने वाले किसानों की सुविधा के लिए मंडियों को 24 घंटे खुला रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आढ़ती वर्ग को राहत देते हुए बताया कि उनका कमीशन 33 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही गुणवत्ता मानकों में राहत देते हुए टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है।

महिलाओं को 33% आरक्षण, 60 वर्ष पर लाइसेंस नवीनीकरण पर रोक

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | राज्य सरकार ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) संशोधन आदेश-2026 जारी कर राशन डिपो (फेयर प्राइस शॉप) के लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। ये आदेश 22 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। सरकार ने राशन डिपो लाइसेंस में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया है। हर तीसरी दुकान महिला को दी जाएगी। हर ब्लॉक में कम से कम 1 डिपो महिला स्वयं सहायता समूह को देने का प्रावधान है। आवेदक का 10+2 पास होना और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान जरूरी है। उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष होगी। जबकि संबंधित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा, परिवार पहचान पत्र जरूरी। सरकारी कर्मचारी, सरपंच-पंच या उनके करीबी रिश्तेदार लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे। अब राशन डिपो के लिए आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किए जाएंगे। पहले की तरह ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी। 60 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा। डिपो धारक की 55 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका लाइसेंस परिवार के किसी सदस्य को दिया जाएगा, बशर्ते सभी शर्तें पूरी हों।

हरियाणा निकाय चुनाव में नियमों के उल्लंघन पर नपेंगे अधिकारी राजनीतिक दलों ने की शिकायत; आयोग ने जारी की गाइडलाइन

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने के बाद सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि यदि कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में प्रचार, समर्थन या सक्रिय भागीदारी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, 13 अप्रैल को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद 22 अप्रैल को राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में यह गंभीर मामला सामने आया कि कुछ स्थानों पर सरकारी कर्मचारी खुले तौर पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर पक्षपात कर रहे हैं। इसे हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 और मॉडल आचार संहिता का सीधा उल्लंघन माना गया है।

चुनावी सभाओं से दूरी बनाएंगे कर्मचारी : आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा और सार्वजनिक सभाओं में उसकी मौजूदगी केवल दर्शक के रूप में और पूर्व अनुमति के साथ ही स्वीकार्य होगी। किसी एक उम्मीदवार की सभाओं में बार-बार उपस्थिति को भी पक्षपात की श्रेणी में रखा जाएगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि कोई मंत्री या राजनीतिक व्यक्ति किसी निजी कार्यक्रम में जाता है, तो सरकारी कर्मचारी उसमें शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयोग ने सिंगल विंडो प्रणाली लागू की है, ताकि उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी 'नो ड्यूज' प्रमाण पत्र जारी करने में जानबूझकर देरी करता है, तो इसे चुनावी निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नीट यूजी: 175 परीक्षा केंद्रों पर 65 हजार 300 विद्यार्थी देंगे परीक्षा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | सीएम नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी 3 मई को होने वाली नीट (यूजी) और 26 अप्रैल को होने वाली एचसीएस परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि इन परीक्षाओं को हर हाल में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए। हरियाणा में नीट परीक्षा के लिए 175 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 65,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्रों पर पीने के पानी, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ अभिभावकों के लिए पार्किंग और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। यातायात प्रबंधन ऐसा हो कि परीक्षार्थी समय पर केंद्र पहुंच सकें; आपात स्थिति में डायल 112 की मदद भी ली जा सकती है। इसके अलावा, केंद्रों पर एंबुलेंस की तैनाती और प्रश्नपत्रों की कड़ी सुरक्षा के आदेश दिए गए हैं।

एनटीए निदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि सुरक्षा व नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए उपकरणों की संख्या दोगुनी की गई है। हर 100 परीक्षार्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर और 48 परीक्षार्थियों पर एक बायोमेट्रिक मशीन होगी। 30 अप्रैल तक सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर लगा दिए जाएंगे। 3 मई को परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी, जिसमें प्रवेश सुबह 11 से दोपहर 1:30 बजे तक ही दिया जाएगा।

हरियाणा में बायोगैस प्लांट में निवेश करेगी सुजुकी

सीएम नायब से सुजुकी के सीईओ ने की मुलाकात, बोले- प्रोग्रेस में करेंगे सहयोग

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सीएम नायब सैनी से गुरुवार को सुजुकी मोटर के सीईओ तोशीहिरो सुजुकी ने मुलाकात की। तोशीहिरो सुजुकी ने कहा कि भारत की प्रोग्रेस के साथ-साथ हरियाणा की प्रोग्रेस में भी उनकी कंपनी पूरा सहयोग करेगी। सीएम नायब ने कहा कि जापान और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए जापान में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया जाएगा। उन्होंने 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में आने के लिए तोशीहिरो को न्योता भी दिया। तोशीहिरो ने कहा कि बायोगैस प्लांट में और अधिक निवेश करने की योजना है। हरियाणा के खरखौदा प्लांट में सुजुकी स्ट्रॉग हाईब्रिड गाड़ियां निर्माण करेंगी। दूसरी ओर, नई उद्योग नीति 2026 पर हरियाणा भवन में हुई बैठक में निवेशकों ने सुझाव दिए। सीएम ने 250-300 एकड़ में टॉय इंडस्ट्री क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। नीति का लक्ष्य संतुलित औद्योगिक विकास, रोजगार वृद्धि व हरियाणा को निवेश हब बनाना है।

महिला आरक्षण बिल पर भाजपा कर रही राजनीति, विपक्ष को बधाई : अभय चौटाला

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री महिला बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने को विशेष सत्र बुला रहे हैं। उनके पास महिला आरक्षण बिल पर निंदा प्रस्ताव लाने का समय है। लेकिन किसानों के लिए नहीं।

जो बिल लोकसभा में गिर गया, उसकी चर्चा यहां पर करने का क्या मतलब है। भाजपा सरकार महिला आरक्षण बिल पर राजनीति कर रही थी। जिसमें वह सफल नहीं हुए। इसको लेकर मैं पूरे विपक्ष को बधाई देता हूं कि उन्होंने भाजपा की मंशा को पूरा नहीं होने दिया। सरकार ने किसानों के लिए एक समस्या और खड़ी कर दी। किसान की जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, उसकी फीस 503 रुपए होती है और अगर किसान की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो यह फीस भी जब्त हो जाती है।

भाजपा ने महिलाओं को आरक्षण देने की सिर्फ बात की : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

अंबाला (राजधानी चौपाल) | नगर निगम चुनाव में अम्बाला सिटी से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कुलविंद्र कौर सैनी का नामांकन दाखिल कराने आए प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। भाजपा ने महिलाओं को आरक्षण देने की सिर्फ बात की, जबकि कांग्रेस ने 5 में से 4 निकायों में मेयर व चेयरमैन पद का टिकट महिलाओं को देकर यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस ही वास्तव में महिलाओं के हितों की सच्ची पक्षधर है। राव नरेंद्र सिंह ने पूर्व विधायक जसबीर मलौर पर कहा कि कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि चुनाव में टिकटों की सूची देर से जारी होती है, लेकिन इस बार पार्टी ने भाजपा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा की है।

पहली पत्नी जिंदा तो दूसरी शादी नहीं होगी मान्य : हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन की मांग की खारिज; सेना अधिकारी से विवाह का किया दावा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होती और उसे शुरू से ही अवैध माना जाता है। ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता न मिलने के कारण उस महिला को पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब महिला को कानूनी रूप से पत्नी का दर्जा ही प्राप्त नहीं है, तो उसे विधवा मानकर फैमिली पेंशन देने का सवाल ही नहीं उठता। यानी, केवल वैध विवाह से जुड़ी पत्नी ही ऐसे लाभों की हकदार होती है।

जीवन में वैवाहिक संबंध निभाएं : मामले में याचिका दायर करते हुए महिला ने दावा कि उसका विवाह एक सेना अधिकारी के साथ हुआ था, लेकिन यह विवाह उस समय हुआ जब अधिकारी की पहली पत्नी जीवित थी और उनकी पहली शादी कानूनी रूप से वैध थी। याची ने दलील दी कि उसने पूरे वैवाहिक जीवन के दौरान अधिकारी के साथ पत्नी की तरह रहकर वैवाहिक संबंध निभाए और समाज में भी उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार किया गया। हिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि समय के साथ अधिकारी की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह अकेली जीवनसंगिनी के रूप में उनके साथ रही। याची का कहना था कि पहली पत्नी के निधन के बाद उसका वैवाहिक संबंध प्रभावी रूप से एकमात्र वैध संबंध बन गया और अब अधिकारी की मृत्यु के बाद उसे विधवा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

हाईकोर्ट में दलील ठुकराई : हालांकि, कोर्ट ने इन सभी दलीलों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि पहली पत्नी के जीवित रहते किया गया विवाह कानून की नजर में शून्य होता है, इसलिए बाद में पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने से भी उस विवाह को वैध नहीं माना जा सकता और न ही इसके आधार पर फैमिली पेंशन का अधिकार दिया जा सकता है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल ने सभी तथ्यों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी व्यक्ति की पहली शादी विधि अनुसार वैध रूप से कायम है और उस दौरान दूसरी शादी की जाती है, तो ऐसी दूसरी शादी कानून की नजर में शुरू से ही शून्य (अवैध) मानी जाती है।

अदालत ने कहा कि इस तरह के अवैध विवाह से महिला को न तो "कानूनी पत्नी" का दर्जा मिल सकता है और न ही बाद में "विधवा" के रूप में कोई अधिकार प्राप्त होता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक संबंधों की वैधता का निर्धारण उस समय की कानूनी स्थिति के आधार पर होता है, जब विवाह किया गया था, न कि बाद में उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर।

कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि फैमिली पेंशन जैसे अधिकार केवल उसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, जिसका वैवाहिक संबंध कानूनन मान्य हो। चूंकि याची का विवाह प्रारंभ से ही अवैध था, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का वैधानिक लाभ, विशेषकर फैमिली पेंशन, प्रदान नहीं किया जा सकता।

मृत्यु से उस संबंध को वैध नहीं बनाया जा सकता

मामला हरियाणा का बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि फैमिली पेंशन का अधिकार पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी वैवाहिक स्थिति कानूनी रूप से क्या थी। यदि उस समय कोई महिला कानूनन पत्नी नहीं मानी जाती, तो उसे बाद में किसी भी आधार पर यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पेंशन जैसे वैधानिक लाभ "मृत्यु के समय मौजूद वैध संबंध" के आधार पर तय होते हैं, न कि बाद में बदलने वाली परिस्थितियों या व्यक्तिगत दावों के आधार पर। इसलिए यदि किसी विवाह को शुरुआत से ही अवैध माना गया है, तो बाद में परिस्थितियों में बदलाव जैसे पहली पत्नी की मृत्यु से उस संबंध को वैध नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने साफ किया कि इस तरह के मामलों में सहानुभूति या सामाजिक परिस्थितियों के बजाय कानून के प्रावधान ही लागू होंगे, और उन्हीं के आधार पर ही फैमिली पेंशन का अधिकार तय किया जाएगा।

एचपीवी वैक्सीन अभियान में तेजी, 13,500 से अधिक किशोरियों को दी जा चुकी

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को राज्यस्तरीय संचालन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए टीकाकरण अभियान के विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 14-15 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 2.26 लाख किशोरियों को कवर करने के लिए 2.28 लाख वैक्सीन डोज की व्यवस्था की गई है। गत 22 अप्रैल तक राज्य में 13,500 से अधिक किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 561 को अभियान के पहले दिन ही टीका लगाया गया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा की सिंगल-डोज टीकाकरण रणनीति भविष्य में इस बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

न्यूज ब्रीफ

हरियाणा सरकार की 1.22 लाख दिव्यांगों को राहत : 40-99% दिव्यांग को भी रोडवेज में मुफ्त यात्रा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा रोडवेज राज्य भर में यात्रियों को सुरक्षित और समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 डिपो और 13 उप-डिपो के नेटवर्क के साथ विभाग करीब 4,108 बसों का संचालन करता है, जो प्रतिदिन लगभग 11.38 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए करीब 6.03 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं। विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के साथ-साथ हरियाणा रोडवेज सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहा है। इसी कड़ी में निगम लगभग 40 श्रेणियों के यात्रियों को मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा देता है। अब राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले वर्ष 2007 में राज्य के भीतर 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को एक सहायक के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई थी, जिसे वर्ष 2010 में चंडीगढ़ और दिल्ली तक विस्तारित किया गया था। दिव्यांगजनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने अब 40 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। राज्य परिवहन विभाग के प्रशासनिक सचिव ने वित्त विभाग से परामर्श के बाद 24 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 1.22 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे दिव्यांगजनों की आवाजाही आसान होगी और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

दिसंबर-2027 तक यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | सीएम नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान घोषणा की कि 2027 के अंत तक यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यमुना में गंदे पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। वर्तमान में यमुना कैचमेंट एरिया में 1543 एमएलडी क्षमता के 91 एसटीपी संचालित हैं, जबकि 11 नए एसटीपी और 8 नए सीईटीपी जल्द स्थापित किए जाएंगे। प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती बरतते हुए सीएम ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत में नए शोधन संयंत्र लगाने के कार्य में तेजी लाने को कहा।

हरियाणा पुलिस की 'अभेद्य' एप के साथ हेल्पलाइन सेवा 01722-930112 नम्बर किया शुरू

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा पुलिस ने अपनी तकनीकी रूप से उन्नत 'अभेद्य' एप के साथ अब एक समर्पित हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल खतरों से त्वरित सुरक्षा व मार्गदर्शन देना है। सहायता के लिए अब लैंडलाइन नंबर 01722-930112 या 24X7 व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर +91 9056555492 पर संपर्क कर सकते हैं। डीजीपी अजय सिंघल ने इसे 'प्रोएक्टिव और रेस्पॉन्सिव पुलिसिंग' का उदाहरण बताते हुए कहा कि पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से उसे घटित होने से पहले ही रोकना है। 'अभेद्य' एप ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय और वर्चुअल नंबरों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करती है।

प्रदेशभर में निकाय कर्मियों ने झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | नगर निकायों के कर्मचारियों ने प्रदेशभर में हाथों में 'उल्टी झाड़' लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री व महासचिव मांगेराम तिगरा ने घोषणा की कि कर्मचारी 27 व 28 अप्रैल को क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। मांगें न माने जाने पर 1 व 2 मई को काम छोड़ो हड़ताल, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। शास्त्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 13 वर्षों से सफाई व सीवर कर्मचारियों की पक्की भर्ती नहीं की है। सफाई का काम 22 वर्षों के लिए ठेकेदारों को सौंपने का निर्णय कर्मचारियों को 'बंधुआ मजदूरी' की ओर धकेलेगा। यूनियन ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य विभागों में ठेका प्रथा खत्म कर कर्मियों को कौशल रोजगार निगम में मर्ज किया गया, सफाई कर्मियों को अब भी ठेकेदारों के शोषण के लिए छोड़ दिया गया है।

राइड-शेयरिंग सेवाओं के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी जल्द

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण कम करने के लिए बहु-क्षेत्रीय कार्ययोजना पर जोर दिया गया। इसके तहत प्रदेश में कैब और राइड-शेयरिंग सेवाओं को विनियमित करने को जल्द 'एग्रीगेटर पॉलिसी' लाई जाएगी, इससे निजी वाहनों का बेड़ा नियामक ढांचे के भीतर आएगा। एनसीआर में डीजल ऑटो लगभग बंद हो चुके हैं व शेष क्षेत्रों में इन्हें 31 दिसंबर 2026 तक हटाया जाएगा। 'नया सफर' योजना के जरिए 1.9 लाख पुराने ट्रकों और 16,000 बसों को बीएस-6, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रमुख शहरों में 'डस्ट-फ्री' सड़कें विकसित करने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए जुलाई 2026 तक निगरानी केंद्रों की संख्या 29 से बढ़ाकर 52 की जाएगी। साथ ही, पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य विभाग में होगी 69 फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही फिजियोथेरेपिस्ट के 69 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) में मांग पत्र भेजा गया है। जींद के गांव उझाना व करनाल के गांव सांभली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दे दी है, इनमें उझाना सीएचसी निर्माण के लिए 2195.46 लाख रुपए की व सांभली सीएचसी के लिए मुख्यमंत्री ने 2322.37 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी या अन्य स्वास्थ्य संस्थान खोलने की आवश्यकता हो, उस गांव में जल्द से जल्द नियमानुसार शुरू किया जाए।

एक ही एफआईआर में दोबारा गिरफ्तारी पर कारण बताना जरूरी नहीं: हाई कोर्ट

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी आरोपी को एक ही एफआईआर में पहले ही गिरफ्तारी के आधार बता दिए गए हैं, तो उसी मामले में दोबारा गिरफ्तारी के समय उन आधारों को फिर से बताना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि एक बार आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दे दी जाती है तो न्यायिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य पूरा हो जाता है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने याचिकाकर्ताओं की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी पुन गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) दायर करने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी। यह मामला फरवरी 2026 में भिवानी के सिविल लाइंस थाना में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई गई थी। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर अदालत परिसर में गोलीबारी जैसे गंभीर आरोप हैं और कुछ आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। ऐसे में पुन गिरफ्तारी को अवैध ठहराने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया का उद्देश्य आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना है न कि उसे तकनीकी आधार पर राहत देना। इसी के साथ याचिका को खारिज कर दिया गया।

संपादकीय...

खून-पसीना किसान का, बेरुखी भगवान की और भेंट चढ़ गया सिस्टम की नाकामी का!

राम-राम भाइयों! की चौपाल में हम उस अन्नदाता के दर्द की बात करेंगे, जिसके साथ कुदरत और व्यवस्था दोनों ने मिलकर एक क्रूर मजाक किया है। किसान की कहानी भी अजीब है—वह हाड़ कंपाने वाली रातों में पानी लगाता है और तपती दोपहर में फसल काटता है, ताकि दुनिया का पेट भर सके। इस बार भी उसने अपनी मेहनत से धरती का सीना चीरकर सोने जैसी गेहूं की फसल पैदा की थी। उसे उम्मीद थी कि इस सुनहरी फसल से उसके घर की तंगहाली दूर होगी, कर्ज का बोझ हल्का होगा और बच्चों के भविष्य की कोई नई राह खुलेगी। लेकिन अफसोस, उसकी उम्मीदों को पहले बेमौसम बारिश ने भिगोया और फिर रही-सही कसर सरकार की नाकामी और मंडियों की घोर अव्यवस्था ने पूरी कर दी।

इस साल जब फसल कटकर खलिहानों तक पहुँचने के लिए तैयार थी, तभी आसमान से बरसी बिन-मौसम बूंदों और ओलावृष्टि ने पकी-पकाई बालियों को मिट्टी में मिला दिया। खेत तालाब बन गए और किसान की महीनों की मेहनत जलमग्न हो गई। लेकिन किसान का हौसला देखिए, उसने हार नहीं मानी। उसने गीली मिट्टी और कीचड़ के बीच से गेहूं के दानों को समेटा, उन्हें सुखाया, साफ किया और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर बड़ी उम्मीद के साथ अनाज मंडी की ओर बढ़ा। उसे लगा था कि मंडी की दहलीज पार करते ही उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सरकार उसकी मेहनत का वाजिब मोल देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि असली नरक तो मंडी के गेट पर उसका इंतजार कर रहा है।

मंडियों का हाल आज किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, जहाँ सरकारी सिस्टम की पोल पूरी तरह खुल चुकी है। शासन की ओर से दावे तो बहुत किए गए थे कि खरीद सुचारू होगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मंडियों में उठान की प्रक्रिया कछुआ चाल से भी धीमी रही। देखते ही देखते मंडियों के प्लेटफॉर्म बोरियों के पहाड़ों से पट गए। जब जगह नहीं बची, तो नया अनाज खुले आसमान के नीचे सड़कों पर डाल दिया गया। अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही का आलम यह रहा कि खुले में पड़ा लाखों क्विंटल गेहूं एक बार फिर बारिश की भेंट चढ़ गया। जो अनाज पहले ही नमी की मार झेल चुका था, वह मंडियों के गंदे पानी और कीचड़ में पड़े-पड़े सड़ने लगा।

हैरानी की बात यह है कि मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद मंडियों में फसल को ढंकने के लिए न तो पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था थी और न ही जल निकासी के उचित प्रबंध किए गए थे। जो गेहूं किसान अपनी जान लड़ाकर और रातों की नींद खराब करके सुखाकर लाया था, वह मंडी के जाम पड़े नालों की गंदगी के कारण वहीं गलने लगा। आज मंडियों से उठने वाली अनाज के सड़ने की बदबू दरअसल हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के सड़ने की गवाह है। किसान अपनी ट्रॉली लिए तीन-तीन दिनों तक गेट पास और खरीद के इंतजार में लाइन में खड़ा रहता है, और इस बीच होने वाली जरा सी भी बारिश उसकी बची-खुची मेहनत को भी मिट्टी में मिला देती है। यह केवल अनाज का नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक परिवार के साल भर के वजूद और उसकी खुशियों का कत्ल है।

प्रशासनिक अधिकारी अक्सर 'नमी' का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और किसानों को प्रताड़ित करते हैं। किसान को कभी पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों में उलझाया जाता है तो कभी गुणवत्ता के नाम पर उसकी उपज को ठुकरा दिया जाता है। सच तो यह है कि अगर समय रहते मंडियों से अनाज का उठान सुनिश्चित किया जाता और उसे सुरक्षित गोदामों तक पहुँचाया जाता, तो आज देश का यह अनमोल धन बर्बाद न होता। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ सरकार अन्न सुरक्षा की बड़ी-बड़ी बातें करती है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपये का अनाज प्रशासनिक सुस्ती के कारण नालियों में बह जाता है।

आज की चौपाल से यह कड़वा सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर इस तबाही का असली जिम्मेदार कौन है? क्या केवल कुदरत को दोष देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है? सरकार को चाहिए कि वह कागजी आंकड़ों के मायाजाल से बाहर निकलकर मंडियों की जमीनी हकीकत देखे। उन किसानों को तुरंत और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनका गेहूं मंडी की बदहाली और उठान न होने के कारण बर्बाद हुआ है। अन्नदाता की जय-जयकार केवल चुनावी नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसके पसीने की कीमत समझना और उसके स्वाभिमान की रक्षा करना शासन का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। अगर आज किसान की ये आह अनसुनी रह गई, तो आने वाले समय में खेती का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

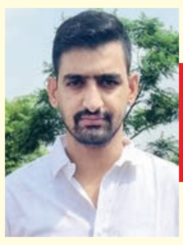

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

तेल संकट बढ़ा तो हम क्या करेंगे...

अमेरिका और ईरान युद्ध शुरू हुए पचास दिन से ज्यादा बीत गए। युद्ध-विराम हुआ भी, तो तेल-गैस की आपूर्ति बहाल न हो पाई। अमेरिका से पाकिस्तान तक दुनिया के ज्यादातर देशों में आर्थिक संकट बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ने लगी है। कुछ असर भारतीय जनजीवन पर भी दिखा है, लेकिन यह संकट अगर और बढ़ा, तो हम क्या करेंगे? जरूरतमंद आबादी को इस संकट से कैसे बचाएंगे?

यह युद्ध अगर जल्दी नहीं रुका, तो क्या होगा? हम संकट का सामना कैसे करेंगे? क्या हम भोजन और ईंधन के पुराने दौर में पहुंच जाएंगे? पुराना दौर अलग था, परिवहन के लिए तेल और भोजन के लिए रसोई गैस पर इतनी निर्भरता नहीं थी। युद्ध शुरू हुए 52 दिन होने को आए, लेकिन युद्ध-विराम के प्रयास कामयाब नहीं हो रहे हैं। आने वाले दिन कैसे होंगे?

पच्चीस-तीस साल पहले भारतीय घरों की रसोई का मतलब सिर्फ भोजन नहीं, धुएं से भरी एक दिनचर्या भी थी। गांवों में लकड़ी, उपले, फसल-अवशेष और कहीं-कहीं मिट्टी तेल की मांग बहुत ज्यादा थी। आधिकारिक सर्वेक्षणों के हिसाब से 1993-94 में ग्रामीण भारत में एलपीजी का उपयोग लगभग 2 प्रतिशत घरों तक सीमित था, जबकि शहरी भारत में 30 प्रतिशत से कम था। साल 2009-10 तक ग्रामीण घरों में एलपीजी लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंची थी; वहीं शहरी भारत में तब एलपीजी 64 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी। साल 2020-21 के मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे में अखिल भारतीय स्तर पर 63 प्रतिशत परिवारों ने साफ ईंधन को खाना पकाने का प्राथमिक स्रोत बताया था। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 तक देश में लगभग 34 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी कनेक्शन, लगभग 10 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन और लगभग डेढ़ करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन थे।

जिस एलपीजी ने लाखों महिलाओं को धुएं से राहत दी, वह एलपीजी पूरी तरह 'घरेलू' नहीं है; उसका रिश्ता वैश्विक तेल और गैस बाजार से है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने साफ कहा है कि हालिया संघर्ष के कारण एलपीजी आपूर्ति श्रृंखलाओं में गंभीर बाधाएं आई हैं, खासकर तब जब गैस-प्रोसेसिंग और समुद्री मार्ग, दोनों दबाव में हैं। इसलिए भारतीय रसोई अब केवल गांव के जंगल, कस्बे के डिपो या शहर के सिलिंडर-गोदाम पर निर्भर नहीं है; वह समुद्री गलियारों, बीमा दरों, जहाजों की आवाजाही, युद्ध की खबरों पर भी निर्भर हो चुकी है और यही नई ऊर्जा-राजनीति है।

युद्ध की लपटें घर तक

आज का संकट सिर्फ तेल-बाजार की रोजमर्रा की हलचल नहीं है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, खासकर ईरान से जुड़ी घटनाओं और होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग व्यवधानों ने बाजार को बार-बार झकझोरा है। अभी क्रूड ऑयल लगभग 111 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंची है। जब समुद्री रास्ता अस्थिर होता है, तब तेल ही नहीं, खाना पकाने की गैस तक असुरक्षित हो जाती है। हमारे पड़ोस की घटनाएं भारत के लिए चेतावनी-पत्र की तरह पढ़ी जानी चाहिए। बांग्लादेश ने 19 अप्रैल 2026 को आयात-लागत बढ़ने के कारण ईंधन मूल्य 10-15 प्रतिशत तक बढ़ाए हैं। युद्ध विराम में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत पाकिस्तान ने अप्रैल के शुरू में डीजल 54.9 प्रतिशत और पेट्रोल 42.7 प्रतिशत तक महंगे कर दिए। श्रीलंका में ईंधन राशनिंग कड़ी की गई है और बिजली दरें भी बढ़ाई गई हैं।

भारत अभी अभाव के उस मोड़ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन यह मान लेना कि हम स्थायी रूप से बचे रहेंगे, ठीक नहीं होगा। संकट पहले सीमापार शुरू होता है, फिर बजट, ट्रांसपोर्ट किराए, खाद्य कीमतों और घरेलू गैस पर दिखता है।

महंगाई देने लगी दस्तक

भारत में भी दबाव के संकेत साफ दिख रहे हैं। मार्च 2026 में खुदरा महंगाई 3.4 प्रतिशत और थोक महंगाई 3.88 प्रतिशत रही। यदि कच्चा तेल लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास लंबे समय तक बना रहा, तो चालू खाते का घाटा 2026-27 में जीडीपी का 2 प्रतिशत तक जा सकता है। वास्तव में, ईंधन संकट सिर्फ पेट्रोल-पंप की समस्या नहीं है, यह मैक्रो इकोनॉमी की समस्या बन जाता है। इसका असर अब उद्योगों तक साफ दिखाई दे रहा है। गैस-निर्भर औद्योगिक क्लस्टरों पर दबाव बढ़ा है, मार्च 2026 में भारत की फैक्टरी गतिविधि धीमी पड़ी है; परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) नरम हुआ है। जब किसी अर्थव्यवस्था में ईंधन महंगा होता है, तो ट्रक का किराया बढ़ता है, कंटेनर महंगे हो जाते हैं, कच्चा या तैयार माल अपने गंतव्य पर देर से पहुंचता है और आखिर में वही बोझ ग्राहक की थाली व जेब में उतरता है।

असल में ईंधन के पूरे सवाल को भावनाओं से नहीं, गणित से समझना होगा। आधिकारिक ऊर्जा आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी 60.21 प्रतिशत, कच्चे तेल की 29.83 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की 6.99 प्रतिशत थी। यानी हमारी ऊर्जा-रचना अब भी जीवाश्म ईंधनों से संचालित है और उसमें तेल की भूमिका बहुत बड़ी बनी हुई है। उससे भी ज्यादा चिंताजनक आयात निर्भरता है। साल 2024-25 में कच्चे तेल की आयात निर्भरता 89.44 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस की 49.73 प्रतिशत और कोयले की 23.50 प्रतिशत रही। यानी हमने ऊर्जा तो बढ़ाई है, पर संप्रभुता उतनी तेजी से नहीं बढ़ाई। उपभोग का महीन हिसाब देखिए, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अप्रैल 2025 में पेट्रोल की खपत 3.45 एमएमटी रही, डीजल 8.28 एमएमटी, एलपीजी 2.52 एमएमटी और प्राकृतिक गैस उपलब्धता/उपभोग 5,847 एमएमएससीएम थी। डीजल का आकार अपने-आप बता देता है कि हमारे यहां माल-ढुलाई, कृषि-उपकरण, बसें, सार्वजनिक परिवहन और औद्योगिक गतिविधियां कितनी गहराई से इस ईंधन पर टिकी हुई है।

हम अक्सर मान लेते हैं कि पेट्रोल-डीजल से सीएनजी की ओर शिफ्ट होना मतलब आयात-निर्भरता से मुक्ति, पर यह आधा सच है। आज भी भारत अपनी प्राकृतिक गैस (नेचुरल गैस) की जरूरतों का लगभग 50-55 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है और इसी आयातित गैस से सीएनजी भी बनाई जाती है।

हरित ईंधन पर कितना भरोसा?

अब सवाल आता है, क्या इलेक्ट्रिक वाहन इस संकट का जवाब हैं? हां, लेकिन पूरा नहीं। नीति आयोग से जुड़ी 2025 की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत में नई वाहन बिक्री का 7.7 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक था और जून 2025 तक भारतीय सड़कों पर 65 लाख ईवी वाहन चल रहे थे।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत दो पहिया और तीन पहिया में अच्छा कर रहा है, इलेक्ट्रिक बसों में भी कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार की रफ्तार धीमी है। वास्तव में, संकट के दौर में ईवी अकेला महामंत्र नहीं है। भारत के ईंधन संकट का संबंध सिर्फ निजी कारों से नहीं है। डीजल-आधारित माल परिवहन, ट्रैक्टर, निर्माण-उपकरण, गैस-पर-चलते औद्योगिक भट्ठे और उर्वरक श्रृंखला - इन सब पर ईवी का असर अभी सीमित है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बस ईवी आ जाए, समस्या खत्म, वे भारतीय ऊर्जा-संकट की जटिलता को छोटा करके देख रहे हैं।

सही बात यह है कि ईवी आयातित तेल पर जरूर चोट करेगा, खासकर शहरों में; पर यह तभी निर्णायक होगा, जब बिजली सस्ती, भरोसेमंद और क्रमशः साफ (कोयला रहित) होती जाएगी।

नई ईंधन नीति की जरूरत

भारत को ईंधन संकट से निपटने के लिए तीन स्तर पर काम करना होगा। पहला काम सुरक्षा-कवच का है। भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि देश के पास अभी 5.33 एमएमटी का पेट्रोलियम रिजर्व है और 6.5 एमएमटी अतिरिक्त क्षमता का प्रस्ताव है। आज के दौर में तेल-भंडार सिर्फ पेट्रो-प्रश्न नहीं, भू-राजनीतिक बीमा है। इसलिए इस भंडार या क्षमता को राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम की तरह लेना चाहिए।

दूसरा स्तर, विविधीकरण का है। हाल में भारत ने एथनॉल के प्रयोग को बढ़ाया है, हमें जैव-ईंधन को और मजबूत बनाना होगा। तीसरा स्तर, मांग में संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। यदि देश का डीजल-नशा तोड़ना है, तो ट्रकों और निजी गाड़ियों से आगे बढ़कर ढुलाई व्यवस्था को बदलना होगा। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 99.2 प्रतिशत विद्युतीकरण की बात कर रहा। इसका मतलब यह है कि ढुलाई को धीरे-धीरे अधिक बिजली-आधारित, रेलवे-आधारित और ईंधन-कुशल बनाया जा सकता है। साल 2014-15 से 2023-24 के बीच सौर ऊर्जा भी 2,05,608 जीडब्लूएच से बढ़कर 3,70,320 तक पहुंची। यानी बिजली का आधार भी धीरे-धीरे बदल रहा है। खैर, हमें रसोई को केंद्र में रखना होगा। ईमानदारी से कहें, तो गरीब परिवार को नेट जीरो उत्सर्जन का व्याख्यान नहीं चाहिए; उसे भरोसेमंद रीफिल, समय पर डिलीवरी और ऐसी कीमत चाहिए, जो उसका हिसाब न बिगाड़े। इसलिए भारत की क्लीन कुकिंग योजना को सिर्फ कनेक्शन ड्रिवेन नहीं, बल्कि रिफिल ड्रिवेन बनाना होगा।

सस्ता ईंधन और सुरक्षित भारत

हमें यह भी समझना होगा कि ऊर्जा-संकट का सबसे बड़ा बोझ हमेशा गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग पर पड़ता है। अमीर परिवार कुछ समय तक महंगा पेट्रोल झेल सकते हैं। बड़ी कंपनियां लागत का बोझ कीमतों में जोड़ सकती हैं, लेकिन छोटा दुकानदार, रिक्शा चालक, किसान, दिहाड़ी मजदूर और सीमित आय वाला परिवार तुरंत दबाव में आ जाता है। यदि रसोई गैस महंगी हुई, तो परिवार फिर लकड़ी, उपले या सस्ते, लेकिन प्रदूषणकारी विकल्पों की ओर लौट सकता है।

यदि डीजल महंगा हुआ, तो माल ढुलाई महंगी होगी, फल-सब्जी महंगी होगी, खेती की लागत बढ़ेगी और महंगाई का एक नया चक्र शुरू होगा। इसलिए ईंधन-नीति को केवल तेल कंपनियों या मंत्रालयों की फाइल का विषय मानना भूल होगी; यह सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता, तीनों का सवाल है। नागरिकों को समझना होगा कि ऊर्जा-सुरक्षा केवल सरकार नहीं बनाती; उसका एक हिस्सा हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से तय होता है। साझा सफर, ऊर्जा-बचत और स्थानीय विकल्पों को अपनाना चाहिए।

क्या भारत ऐसी अर्थव्यवस्था बन रहा है, जो किसी युद्ध, समुद्री अवरोध या वैश्विक झटके के बीच भी अपनी रसोई, अपनी बस, अपना ट्रक, अपना खेत और अपनी फैक्टरी चलाती रह सके। विकसित भारत की कसौटी सस्ता पेट्रोल नहीं, लचीली ऊर्जा-व्यवस्था है। वह व्यवस्था जो आयातित तेल के झटकों को झेल जाए, ईवी को तेजी से बढ़ाए, रणनीतिक भंडार भरे, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दे और गरीबों को धुएं की तरफ वापस लौटने पर मजबूर न करे।

संकट हमारे सामने है, लेकिन रास्ता भी वहीं है - कम खपत, समझदार खपत, विविध खपत और घरेलू क्षमताओं का तेज विस्तार। अगर हमने यह नहीं किया, तो अगला युद्ध सिर्फ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगा; वह हमारे महीने का बजट लिखेगा। अगर हमने यह कर लिया, तो ईंधन संकट भी विकसित भारत की यात्रा को रोक नहीं पाएगा। **-लेखक के अपने विचार हैं**

भारत में क्यों चिंता?

» भारत में 90 प्रतिशत लोग क्रय शक्ति में पर्याप्त सक्षम नहीं हैं।

» भारत में करीब 14 करोड़ लोग ही क्रय शक्ति में पूरी तरह सक्षम हैं।

» गांव में आम नागरिक 4,000 रुपये से कम में महीना गुजारते हैं, जबकि शहर में 6,500 रुपये में।

रसोई : भोजन पकाने पर बढ़ता संकट

भारत में लगभग 90 प्रतिशत घरों तक रसोई गैस की पहुंच हो गई है, लेकिन अभी केवल 62 प्रतिशत लोग पूरी तरह से रसोई गैस पर निर्भर हैं। बाकी लोग रसोई के लिए अन्य ईंधन का सहारा लेते हैं। रसोई गैस की कीमत बढ़ते ही, उन लोगों पर सर्वाधिक असर पड़ता है, जो कुशल मजदूर नहीं हैं। जिनकी आय ज्यादा नहीं है। ऐसे मजदूर रसोई गैस की किल्लत होते ही, अपने गांव-घर की ओर लौटने को मजबूर हो जाते हैं। गांव पहुंचकर उन्हें भोजन पकाने के अन्य विकल्प या ईंधन मिल जाते हैं। सूरत, दिल्ली से लौटने वाले मजदूरों का कहना है कि काला बाजार में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 4,000 रुपये तक पहुंच जा रही है। अकेले गुजरात से ही लाखों मजदूर लौट आए हैं, जिससे वहां श्रमिकों का अभाव हो गया है। ऐसे में, अगर खाड़ी देशों में युद्ध बढ़ता है या ईंधन महंगा होता है, तो श्रमिकों पर सर्वाधिक असर पड़ने की आशंका है।

परिवहन : तेल के दाम बढ़ने से समस्या

जब अमेरिका में तेल पेट्रोल-डीजल के भाव में 30 प्रतिशत तक की बढ़त हुई है, तब भारत किसी तरह से सामान्य ईंधन के भाव को बढ़ने से रोके हुए है। अमेरिका जैसा सक्षम देश दिसंबर से अभी तक गैस की कीमतों में 47 प्रतिशत की वृद्धि को रोक नहीं पाया है। वहां महंगाई 4 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर रही है। ऐसे में, भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती चिंता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। महंगाई भारत में भी बढ़ रही है और अगर पेट्रोल, डीजल के भाव में वृद्धि हुई, तो कीमतों में और तेजी आ जाएगी। यात्रा खर्च बढ़ेगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, तो आम भारतीयों पर सीधे असर पड़ेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि युद्ध अगर नहीं रुका, तो भारतीय विकास पर असर पड़ेगा। डॉलर की कीमत बढ़ रही है, निवेश कम हो रहा है और लोग भी बजट में कटौती करने लगे हैं।

लेखक : राहुल हिंदुस्तानी

बीकाजी फूड्स के चेयरमैन शिव रतन अग्रवाल जी को श्रद्धांजलि

शिव रतन कहते थे- मशीनें सिर्फ रफ्तार बढ़ाती हैं, संस्कार नहीं; तकनीक अपनाएं... पर अपनी जड़ों को मत छोड़िए....

बीकानेर की उन तंग गलियों में जहाँ कभी मोठ और बेसन की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी, वहाँ से निकलकर सात समंदर पार तक स्वाद का साम्राज्य खड़ा कर देना कोई मामूली बात नहीं है। यह कहानी है उस शख्स की, जिसने न केवल व्यापार किया बल्कि एक संस्कृति को पैकेट में बंद कर दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाया। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन शिव रतन अग्रवाल, जिन्हें दुनिया 'फन्ना बाबू' के नाम से जानती थी, अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 वर्ष की आयु में चेन्नई में उनका निधन एक युग का अंत है। वे अपनी पत्नी की बाईपास सर्जरी के बाद वहाँ रुके थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शिव रतन जी का जाना केवल एक उद्योगपति का जाना नहीं है, बल्कि उस 'स्वाद की शुचिता' के संरक्षक का जाना है जिसने भारतीय नमकीन उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाई।

विरासत से आगे: अपनी लकीर खींचने का साहस

शिव रतन अग्रवाल का जन्म उस परिवार में हुआ था जिसका नाम 'हल्दीराम' के रूप में पहले ही दुनिया भर में प्रसिद्ध था। चाहते तो वे उस विशाल वटवृक्ष की छाँव में आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ अपना, कुछ मौलिक करने की तड़प थी। 1993 में उन्होंने 'हल्दीराम' समूह से अलग होकर 'बीकाजी' की नींव रखी।

अक्सर लोग विरासत को अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं, पर शिव रतन जी का मानना था कि विरासत केवल एक बुनियाद है, महल आपको खुद खड़ा करना पड़ता है। वे गर्व से कहते थे, "हल्दीराम जी ने मुझे व्यापार की बारीकियां सिखाईं, लेकिन बीकाजी ने मुझे मेरा नाम और पहचान दी।" उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब तक आप अपनी मेहनत से एक नई और बड़ी लकीर नहीं खींचते, तब तक दुनिया आपकी गिनती नहीं करती। आज 17,282 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली कंपनी उनके उसी अटूट संकल्प का प्रमाण है।

मशीनीकरण और स्वाद का संतुलनः तकनीक में समाया संस्कार : एक दौर था जब माना जाता था कि भुजिया का असली स्वाद केवल हाथों के हुनर से ही आ सकता है। जैसे-जैसे व्यापार बढ़ा, मशीनीकरण की जरूरत महसूस हुई। यहाँ शिव रतन जी ने एक नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने आधुनिक मशीनों को कारखानों में जगह तो दी, लेकिन स्वाद की 'पवित्रता' से समझौता नहीं किया।

उनका दर्शन बड़ा स्पष्ट थाः "मशीनें रफ्तार बढ़ा सकती हैं, पर संस्कार नहीं।" उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मशीन से निकलने वाली भुजिया भी वही तृप्ति दे, जो कभी बीकानेर की गलियों में हाथ से बनी भुजिया देती थी। उन्होंने तकनीक को अपनी जड़ों (स्वाद) पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि आज बीकाजी के पास 250 से ज्यादा वैरायटी होने के बावजूद, हर उत्पाद में वही पारंपरिक भारतीय जायका मिलता है।

सांस्कृतिक राजदूतः बीकानेर से वैश्विक बाजार तक : शिव रतन जी ने कभी खुद को महज एक 'नमकीन विक्रेता' नहीं माना। उनकी सोच बहुत व्यापक थी। उन्होंने हमेशा कहा कि वे बीकानेर की मिट्टी और वहाँ की संस्कृति को एक पैकेट में पैक करके दुनिया को दे रहे हैं। इसी सोच ने बीकाजी को एक वैश्विक ब्रांड बनाया। आज 40 से अधिक देशों में यदि कोई बीकाजी का पैकेट खोलता है, तो उसे केवल नमकीन नहीं, बल्कि राजस्थान की गौरवशाली परंपरा का अनुभव होता है। उन्होंने बीकानेरी भुजिया को केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि एक 'ग्लोबल आइकन' बना दिया।

अनुशासन और भरोसे का चेहराः ब्रांड एंबेसडर के रूप में अमिताभ : जब बीकाजी ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया, तो इसके पीछे केवल विपणन की रणनीति नहीं थी। शिव रतन जी अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व में छिपे अनुशासन और भरोसे के कायल थे। वे चाहते थे कि जब कोई ग्राहक बीकाजी का पैकेट उठाए, तो उसे वही भरोसा हो जो अमिताभ की 'क्लास' और 'क्वालिटी' पर है। यह उनकी दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने ब्रांड को एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जोड़ा जो विश्वसनीयता का दूसरा नाम है।

सादगी और सेवाः फन्ना बाबू का मानवीय पक्ष : व्यापारिक जगत में अरबपति होने के बावजूद, शिव रतन अग्रवाल जी ने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। करीबियों के बीच वे हमेशा 'फन्ना बाबू' रहे—एक ऐसा इंसान जो जितना बड़ा अपने काम में था, उतना ही विनम्र अपने व्यवहार में। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची (2024) में स्थान बनाना और 13,175 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत नेटवर्थ होना उनके लिए केवल आंकड़े थे। उनका असली धन वह दुआएं थीं, जो उन्होंने अपनी सेवा और सादगी से कमाई थीं। बीकानेर के समाज और व्यापारिक जगत में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने न केवल हजारों लोगों को रोजगार दिया, बल्कि उद्यमिता की एक ऐसी पाठशाला खड़ी की जहाँ ईमानदारी और गुणवत्ता ही एकमात्र पाठ्यक्रम है।

एक युग का अवसान : शिव रतन अग्रवाल जी का निधन भारतीय उद्योग जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने 33 साल के अपने स्वतंत्र सफर में बीकाजी को जिस ऊंचाई पर पहुँचाया, वह शोध का विषय है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुँचकर भी अपनी जड़ों को कैसे थामे रखना है।

पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की सीधी बातचीत पर पेंच : ईरान बोला- पाक को अपनी शर्तें सौंपेंगे; अमेरिका को मीटिंग की उम्मीद

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल)| अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां भेजा है। वे आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं, उन्हें स्टैंडबाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वे इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे 11-12 अप्रैल को अमेरिका-ईरान की पहली बातचीत में डेलिगेशन के प्रमुख थे।

व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी डेलिगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। यानी बातचीत अगर होगी भी, तो आमने-सामने नहीं बल्कि बीच में पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करेगा। यानी एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान साफ इनकार कर रहा है।

पहले दौर की बातचीत फेल हुई थी

पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक यह वार्ता चलने के बावजूद नाकाम हो गई थी। दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। अमेरिका चाहता है कि यहां से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खुली और सुरक्षित रहे, ताकि तेल सप्लाई में रुकावट न हो। वहीं ईरान इस इलाके पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है और इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, ताकि वह परमाणु हथियार न बना सके। लेकिन ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण (जैसे बिजली बनाने) के लिए है और वह इसे बंद नहीं करेगा।

ईरान में गालिबाफ को डेलिगेशन से हटाने की चर्चा

तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बातचीत करने वाली टीम में अंदरूनी मतभेद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बाघेर गालिबाफ को बातचीत टीम से हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह यह बताई जा रही है कि वे अमेरिका के साथ बातचीत में परमाणु मुद्दे को शामिल करना चाहते थे। इसका मतलब है कि वे इस बात पर चर्चा के लिए तैयार थे कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ शर्तें मान सकता है या उस पर बातचीत हो सकती है। इससे कट्टरपंथी धड़ा नाराज हो गया। अब खबर यह भी है कि उनकी जगह सईद जलीली को लाया जा सकता है, जिन्हें ज्यादा सख्त रुख वाला नेता माना जाता है। सईद जलीली ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था लेकिन वे मसूद पजशकियान से हार गए थे। IRGC में उनका बहुत असर माना जाता है। एक दशक पहले पश्चिमी देशों और ईरान के बीच जो परमाणु हथियारों पर बातचीत हुई थी वो उसके वार्ताकार रहे हैं। परमाणु हथियार को लेकर उनका आक्रामक रुख रहा है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि ईरान के अंदर दो लाइनें चल रही हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो बातचीत को थोड़ा लचीला बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सख्त रुख रखना चाहते हैं, खासकर परमाणु मुद्दे पर।

ईरान में IRGC ने 240 लोगों को गिरफ्तार किया

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने दो प्रांतों में छापेमारी कर करीब 240 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अल जजीरा के मुताबिक, कुर्दिस्तान प्रांत में 11 लोगों को पकड़ा गया और एक कुर्दिश आर्म्ड ग्रुप के सदस्य को मार गिराने का दावा किया गया है। इसके अलावा हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए और अलग-अलग छापों में करीब 70 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, केरमानशाह प्रांत में 155 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें 'काउंटर-रिवोल्यूशनरी समूहों' से जुड़ा बताया गया है। इनमें चार लोग ऐसे भी हैं, जिन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी 'मोसाद' से जुड़े होने का आरोप है। तेहरान में भी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर मिसाइल हमलों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर दुश्मन नेटवर्क को देने का आरोप है।

दक्षिण लेबनान में लौटने पर फिर इजराइल की चेतावनी

इजराइल की सेना (IDF) ने दोहराया है कि वह दक्षिण लेबनान के बड़े हिस्से पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और वहां से लोगों को वापस न लौटने की चेतावनी दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के प्रवक्ता अविचय अद्राई ने दर्जन गांवों की सूची जारी कर कहा कि लितानी नदी, वादी सलहनिया और सलूकी जैसे इलाकों के पास जाना प्रतिबंधित है।

तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद उनका देश होर्मुज स्ट्रेट में माइन हटाने के अभियान में शामिल हो सकता है। लंदन में उन्होंने कहा कि यह काम अलग-अलग देशों की तकनीकी टीम मिलकर करेगी और तुर्किये को इसमें भाग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर भविष्य में ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय टीम सीधे संघर्ष का हिस्सा बनती है, तो तुर्किये अपने रुख की फिर से समीक्षा करेगा। फिदान ने यह भी कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान में होने वाले अगले दौर की बातचीत में समाधान निकल सकता है।

अमेरिका बोला- होर्मुज पर कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए जरूरी है और इस अहम रास्ते से अमेरिकी परमिशन के बिना कोई नहीं गुजर सकता। पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों पर लगी नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना छोड़ नहीं देता। साथ ही, उन्होंने यूरोप और एशिया के देशों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे है।

सीजफायर के बीच ईरान ने तेहरान एयरपोर्ट खोला

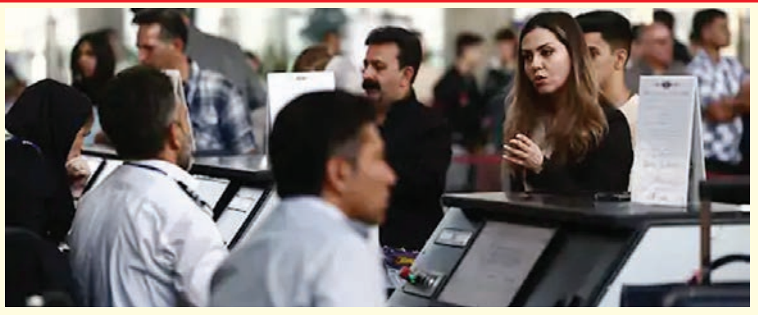

ईरान ने संघर्षविराम के बीच तेहरान का मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमाम खुमैनी को फिर से खोल दिया है और उड़ानें दोबारा शुरू कर दी हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी एयरलाइंस की ये उड़ानें शनिवार को इस्तांबुल और मस्कट के लिए रवाना हुईं। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब क्षेत्र में सीजफायर लागू है। युद्ध के कारण कई हफ्तों से एयर ट्रैफिक प्रभावित था। अधिकारियों ने कहा है कि धीरे-धीरे और भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएंगी, ताकि हवाई सेवाएं सामान्य हो सकें।

ईरान बोला- हम 1,000 से ज्यादा तरह के हथियार खुद बना रहे

ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलायी-निक ने कहा है कि ईरान अब देश के अंदर ही 1,000 से ज्यादा तरह के हथियार बनाता है। उन्होंने बताया कि इन हथियारों में मिसाइल, ड्रोन और कई तरह के सैन्य सिस्टम शामिल हैं, और इनका उत्पादन पूरी तरह घरेलू स्तर पर होता है। तलायी-निक के मुताबिक, यह क्षमता 25 साल से ज्यादा समय तक रक्षा क्षेत्र में किए गए निवेश का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि हथियार बनाने की सुविधाएं पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर फैली हुई हैं। इसका फायदा यह है कि अगर कुछ ठिकानों को नुकसान भी हो जाए, तो भी उत्पादन जारी रखा जा सकता है।

ट्रम्प बोले—होर्मुज में माइन बिछा रहे जहाजों को तबाह करें : होर्मुज हमारे नियंत्रण में, परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल)| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैंने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया कि होर्मुज में बारूदी सुरंगें (माइन) बिछा रहे छोटे से छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट तबाह कर दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि बारूदी सुरंग हटाने वाले उनके जहाज स्ट्रेट को साफ कर रहे हैं। उन्होंने इस काम को तीन गुना तेजी से करने का आदेश दिया है।

दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिकी नेवी की परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता है। जब तक ईरान किसी समझौते पर नहीं आता, तब तक स्ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। ईरान युद्ध में बुरी तरह हार रहा है।

ट्रम्प बोले- ईरान संघर्ष में परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कहा है कि वह ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हथियार किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ट्रम्प ने यह बात व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

जब ट्रम्प से पूछा गया कि क्या वह ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया- ऐसा बेवकूफी भरा सवाल क्यों पूछा जा रहा है... नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। परमाणु हथियार किसी के द्वारा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

ट्रम्प ने इस दौरान अमेरिका की आर्थिक स्थिति और तेल आपूर्ति को लेकर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास मजबूत अर्थव्यवस्था और पर्याप्त तेल संसाधन हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि कई जहाज अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बजाय अमेरिका की ओर आ रहे हैं। यह कदम ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच देखा जा रहा है।

ट्रम्प बोले- अमेरिका में कुछ समय के लिए ईंधन महंगा होगा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि देश में ईंधन की कीमतें कुछ समय के लिए बढ़ेंगी। उन्होंने इसे US-इजराइल युद्ध की छोटी कीमत बताते हुए कहा कि यह कदम ईरान से जुड़े खतरे को खत्म करने के लिए जरूरी है।

ट्रम्प के मुताबिक, निकट भविष्य में फ्यूल प्राइस बढ़ना तय है, लेकिन इसे अस्थायी माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी लंबे समय के रणनीतिक फायदे के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि इस युद्ध का मकसद ईरान के खतरे को खत्म करना और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।

ईरान पर ट्रम्प का फिर सख्त बयान : बोले- जरूरत पड़ी तो एक दिन में खत्म करेंगे

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान ने सीजफायर के दौरान अपनी सैन्य ताकत कुछ हद तक फिर से तैयार की हो सकती है, लेकिन US उसे "एक दिन में खत्म" कर सकता है। उन्होंने साफ किया कि ईरान के साथ किसी दीर्घकालिक समझौते को लेकर उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है।

ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान की नौसेना, एयरफोर्स और एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम पहले ही खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा- हो सकता है उन्होंने दो हफ्ते के ब्रेक में कुछ तैयारी की हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसे एक दिन में खत्म कर देंगे।

वहीं, जब उनसे ईरान के साथ दीर्घकालिक समझौते की समय-सीमा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा- जल्दी मत करिए। इससे साफ है कि अमेरिका फिलहाल जल्दबाजी में कोई डील करने के मूड में नहीं है और हालात के हिसाब से ही आगे के फैसले लिए जाएंगे।

ट्रम्प बोले- ईरान से समझौता तभी जब US के लिए सही : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ कोई भी समझौता तभी होगा, जब वह अमेरिका के लिए "उचित और फायदेमंद" होगा। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है और फैसला पूरी तरह अमेरिकी हितों पर निर्भर करेगा।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि "हमारे पास दुनिया भर का समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं है – समय तेजी से निकल रहा है। ट्रम्प ने अमेरिकी मीडिया पर भी निशाना साधा, जिसने यह संकेत दिया था कि वह युद्ध खत्म करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका पर कोई दबाव नहीं है।

उन्होंने फिर से दावा किया कि युद्ध में ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक, ईरान की नौसेना समुद्र में खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स नष्ट हो गई है और एंटी-एयरक्राफ्ट व रडार सिस्टम भी खत्म हो चुके हैं।

ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान के कई नेता अब नहीं रहे और अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह मजबूत है। उन्होंने चेतावनी दी कि हालात आगे और खराब हो सकते हैं और समय ईरान के पक्ष में नहीं है।

भारत ने नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी

भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को हवाई और जमीनी दोनों रास्तों से ईरान जाने से बचना चाहिए।

सरकार ने अपने एडवाइजरी में कहा कि ईरान के लिए सीमित फ्लाइट्स शुरू होने के बावजूद एयरस्पेस प्रतिबंध और ऑपरेशनल अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जो यात्रियों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी गई है। इसके लिए निर्धारित जमीनी मार्गों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नागरिक किसी भी सीमा पार करने से पहले भारतीय दूतावास के साथ समन्वय जरूर करें, ताकि सुरक्षित तरीके से बाहर निकला जा सके।

जंग से बढ़ेगा वैश्विक गरीबी संकट : 3 करोड़ लोग गरीबी में जा सकते हैं

ईरान युद्ध के असर से दुनिया भर में गरीबी और खाद्य संकट बढ़ने का खतरा है। UNDP के प्रमुख अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा है कि इस युद्ध के चलते 3 करोड़ से ज्यादा लोग फिर से गरीबी में जा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युद्ध तुरंत भी खत्म हो जाए, तब भी इसके असर लंबे समय तक बने रहेंगे।

डी क्रू ने कहा कि ईंधन और खाद (फर्टिलाइजर) की सप्लाई में आई बाधाओं का असर सीधे गरीब देशों और लोगों पर पड़ेगा। डी क्रू के अनुसार, आने वाले कुछ महीनों में वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा अपने चरम पर पहुंच सकती है और इसे रोकने के लिए बहुत कम विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस संकट का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। अनुमान के मुताबिक, दुनिया के GDP का 0.5% से 0.8% तक नुकसान हो चुका है। डी क्रू ने कहा कि जो आर्थिक और सामाजिक विकास दशकों में होता है, उसे सिर्फ कुछ हफ्तों के युद्ध से खत्म किया जा सकता है।

युद्ध लंबा खिंचने की आशंका से तेल महंगा

मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चलने की आशंका के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड करीब 1.9% बढ़कर लगभग 104 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। यह लगातार चौथे दिन बढ़ा। वहीं WTI भी बढ़कर करीब 94.6 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता न होने से निवेशक अब लंबे संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के लंबे समय तक बंद रहने की आशंका मान रहे हैं। इसका असर शेयर बाजारों पर भी पड़ा है। अमेरिका में S&P 500 और Nasdaq के फ्यूचर्स कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। यूरोप के बड़े बाजारों में भी गिरावट है, जबकि एशिया में जापान और हांगकांग के बाजार नीचे बंद हुए, वहीं दक्षिण कोरिया का बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ।

इजराइल की पूरी वापसी तक बातचीत नहीं

लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने साफ कहा कि इजराइल की पूरी वापसी के बिना उनका देश कोई समझौता नहीं करेगा। यह बयान वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत से पहले आया। अल जजीरा के मुताबिक, उन्होंने कहा कि लेबनान किसी बफर जोन या ऐसी इजराइली मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा, जहां विस्थापित लोग वापस न लौट सकें और नष्ट हुए शहरों-गांवों का पुनर्निर्माण न हो सके। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मेक्रो से मुलाकात के दौरान दिए इंटरव्यू में सलाम ने कहा कि अमेरिका ही ऐसा पक्ष है जो इजराइल पर दबाव डाल सकता है। सीजफायर कराने में अमेरिका की भूमिका अहम रही और उम्मीद है कि वह आगे भी इजराइल पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा।

- **लेबनान- हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना आसान नहीं :** लेबनान की स्वतंत्र सांसद नजात आउन सलीबा ने कहा कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना लंबी प्रक्रिया है और यह रातोंरात संभव नहीं है। अल जजीरा के मुताबिक, उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों में लेबनानी सेना को पर्याप्त संसाधन नहीं मिले, जबकि हिजबुल्लाह लगातार मजबूत होता गया।

ईरान जंग में खर्च हुईं चीन के लिए रिजर्व मिसाइलें

अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब; हर दिन 90 अरब खर्च

वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | ईरान के साथ 38 दिन चले युद्ध में अमेरिका ने अपनी कई अहम और महंगी मिसाइलें खर्च कर दीं। इनमें वो मिसाइलें भी शामिल हैं, जो चीन जैसे बड़े देशों से होने वाले संभावित युद्ध के लिए संभालकर रखी गई थीं। अब अमेरिका का हथियार भंडार तेजी से कम हो रहा है। इस युद्ध में अमेरिका ने करीब 1100 लंबी दूरी की स्टील्थ मिसाइलें (JASSM-ER) इस्तेमाल कीं। ये खास तौर पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाई गई थीं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें, 1200 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें और 1000 से ज्यादा दूसरी स्ट्राइक मिसाइलें भी दागी गईं। इस पूरे युद्ध पर 28 से 35 अरब डॉलर खर्च हुए। यानी हर दिन करीब 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपए) खर्च हुए। युद्ध रुके हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने यह नहीं बताया कि कुल कितने हथियार इस्तेमाल हुए। मंत्रालय का कहना है कि 13,000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया गया। लेकिन अधिकारियों के मुताबिक एक ही टारगेट पर कई बार हमले हुए, इसलिए असल में इस्तेमाल हुए हथियारों की संख्या इससे काफी ज्यादा है।

मिसाइलों का स्टॉक तेजी से कम हुआ : युद्ध के दौरान अमेरिका ने जिन हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, उनमें लंबी दूरी की JASSM-ER मिसाइलें शामिल हैं। ये 600 मील से ज्यादा दूर तक मार कर सकती हैं और दुश्मन की एयर डिफेंस से बचकर हमला करने के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा टॉमहॉक मिसाइलों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। अमेरिका सालभर में जितनी मिसाइलें खरीदता है, उससे करीब 10 गुना ज्यादा इस युद्ध में खर्च हो गईं।

व्हाइट हाउस ने हथियार खत्म होने का दावा खारिज किया

व्हाइट हाउस ने हथियार खत्म होने के दावों को गलत बताया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है और उसके पास पर्याप्त हथियार हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने भी किसी खास इलाके या हथियारों के स्टॉक की जानकारी देने से इनकार किया। उन्होंने इसे सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया। युद्ध के पहले दो दिनों में ही 5.6 अरब डॉलर के हथियार इस्तेमाल हो गए थे। इसके अलावा कुछ ऑपरेशन में नुकसान भी हुआ। ईरान से पायलट को निकालने के मिशन में दो MC-130 विमान और तीन हेलीकॉप्टर नष्ट करने पड़े, जिनकी कीमत करीब 275 मिलियन डॉलर बताई गई।

ब्लड प्रेशर काबू रखने में दवाओं की बड़ी भूमिका है। हालांकि, कई बार दवा लेने के बावजूद ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। मौसम, प्रदूषण, शारीरिक स्थिति, जीवनशैली से लेकर दवा लेने में लापरवाही जैसी कई बातें ब्लड प्रेशर के स्तर पर असर डाल सकती हैं...

दवा के बावजूद अगर बढ़ा रहे बीपी...

विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत पर रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 22 करोड़ लोगों को हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन की समस्या है। इनमें से केवल 12 प्रतिशत ही अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रित रख पाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़ें भी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश करते हैं। इसके बावजूद भारत में इलाज कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल दर 12 से 13 प्रतिशत ही है।

एक अन्य अध्ययन के अनुसार, देश में हर चार में से एक वयस्क को हाई ब्लड प्रेशर है। इसकी मौजूदगी पुरुषों, शहरी इलाकों, अधिक उम्र के लोगों (60 से ज्यादा) में अधिक देखने को मिल रही है। बीते दो दशक में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कमजोर लोगों में भी अब उच्च रक्तचाप के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी चिंता जताते हैं कि कुछ मरीजों में दवा लेने के बावजूद ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है।

अगर इलाज न करे असर

1. **समस्या को नए सिरे से समझें** : समस्या व ज्यादातर लोग तनाव या दवा की गलत डोज को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का जिम्मेदार मानते हैं। यह एक खास स्थिति है, जिसमें तीन या ज्यादा दवाएं, जिसमें एक पेशाब वर्द्धक दवा भी शामिल होती है, लेने के बावजूद व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। ऐसे में असली कारण का पता लगाए बिना बार-बार दवा की खुराक बदलना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले गहन जांच जरूरी है।

2. **दवा और जांच में मनमर्जी न करें** : हार्ट जर्नल के अनुसार, हाइपरटेंशन वाले 50 से 80% लोग डॉक्टर के बताए अनुसार बीपी की दवा नहीं लेते हैं। दवा का महंगा होना, गलत जानकारी के कारण लोग दवा सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, जो समस्या बढ़ा देता है। ज्यादातर मरीज नियमित बीपी जांच में भी लापरवाही बरतते हैं।

3. **दूसरे कारकों की भी भूमिका पर ध्यान दें** : कभी-कभी शरीर के अंदर होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया भी हाई बीपी का कारण बन जाती है। ओवरएक्टिव सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को तनाव में रखता है, जिससे इलाज के बावजूद ब्लड प्रेशर में आराम नहीं मिलता। किडनी की बीमारी, हार्मोनल असंतुलन (जैसे थायरॉइड फंक्शन से जुड़ी समस्या) या अनिद्रा जैसे कारक हाई ब्लड प्रेशर काबू होने नहीं देते हैं। कुछ दवाएं जैसे दर्द निवारक, स्टेरॉएड और एंटीडिप्रेसेंट, खराब जीवनशैली, ज्यादा नमक, शराब व धूम्रपान करना, वजन बढ़ना या लगातार तनाव भी स्थिति बिगाड़ देते हैं।

अगर बीपी नियंत्रित नहीं रहता, तो इंटरवेंशनल इलाज के विकल्प उभर रहे हैं। इनमें से एक है रीनल डिनरवेशन। यह एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है, जिसमें किडनी के आसपास की ओवरएक्टिव नसों को निष्क्रिय करके ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है।

सर्दी में बढ़ न जाए समस्या

इंडियन हार्ट जर्नल के एक लेख के अनुसार, उत्तरी भारत में हुई रिसर्च में पाया गया कि ठंड में लोगों में हाई बीपी की समस्या 23.72% हो गई, जबकि गर्मियों में यह दर 10.12% थी। बच्चों में भी ऐसा पैटर्न रहा, उनमें ठंड में 29.4% बीपी बढ़ने का मामला मिला, जो गर्मियों के 18.7% के मुकाबले ज्यादा था।

ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है, जिससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी में उतार-चढ़ाव होता है। इसके अलावा, ठंड में लोग कम सक्रिय होते हैं, प्रदूषण बढ़ जाता है व लोग अधिक तला-भुना खाते हैं। इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठंडा तापमान सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिम्युलेट कर सकता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हृदय गति बढ़ाते हैं और नसों को संकुचित करते हैं।

ब्लड प्रेशर को जानें : जब दिल खून को पंप करता है, तो इसका दबाव धमनियों की दीवारों पर बनता है, यह दबाव ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर में दिल सिकुड़ता है। यह ब्लड प्रेशर का ऊपर का नंबर है। जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम करता है, तो नीचे का नंबर या डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। एक सामान्य रीडिंग आमतौर पर 120/80 एमएम एचजी से कम होती है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन 130/80 एमएम एचजी उससे ज्यादा होती है। हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड का दबाव लगातार बहुत अधिक रहता है, जिससे धमनियों को नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर स्ट्रोक, किडनी और दिल की बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

क्या है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन?

सही दवा और एहतियात के बावजूद ब्लड प्रेशर ज्यादा बना रहता है, तो इसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहा जाता है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होना संकेत है कि हमें ब्लड प्रेशर की गहराई से जांच कराए जाने की जरूरत है। यह सेकेंडरी कारणों जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या हार्मोनल असंतुलन या ब्लड प्रेशर को मापने और समझने के तरीके में समस्याओं का संकेत दे सकता है। लगातार बढ़े हुए बीपी की अनदेखी करना खतरनाक हो सकता है।

जरूरत पड़ जाए तो करें उपाय

- तुरंत आराम करें और तनाव कम करें
- नमक का सेवन तुरंत कम कर दें
- बीपी मॉनिटर करते रहें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा समय पर लें
- बहुत ठंड में जाने से बचें। कैफीन और शराब का सेवन नहीं करें।
- यदि बीपी 180/120 से अधिक है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

दवाओं की अहम भूमिका

- दवा का चुनाव व्यक्तिगत सेहत, उम्र, दिल व किडनी की स्थिति के आधार पर करते हैं। कुछ मरीजों में खून के थक्के बनने का खतरा होता है। ऐसे में उन्हें एंटीकोआगुलेंट्स (खून पतला करने की दवा) दी जाती हैं। पर सबको इसकी जरूरत नहीं है। खुद से इसे लेने से रक्तस्राव हो सकता है।
- सब पर एक ही दवा समान रूप से असर नहीं करती है। हाल के सालों में कई नए कंबाइंड फार्मूलेशन लॉन्च हुए हैं। इससे मरीजों को कम गोलियां लेनी पड़ती हैं।
- बीपी की दवा कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में ही लें।

रखिए पूरा ध्यान...

1. नियमित निगरानीः जिन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग हैं या 40 साल से अधिक उम्र हैं, वे नियमित बीपी की जांच करें। आप घर भी जांच कर सकते हैं। लगातार बीपी बढ़ा रहे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

2. सही दवा समय पर लेंः व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बीपी की अलग-अलग दवाएं होती हैं, जैसे शरीर से ज्यादा सोडियम और पानी निकालने में मदद कर या ब्लड वेसल्स को आराम देकर बीपी कंट्रोल करने वाली दवाएं, इसलिए डॉक्टर से पूछ कर ही दवा ले।

3. संतुलित डाइटः साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियां, दालें, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएं। नमक कम खाएं। प्रोसेस्ड फूड, अचार, पनीर आदि कम खाएं। फाइबर व ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे ओट्स, दलहन, अखरोट व अलसी खाएं। तली-भुनी व मैदे से बनी चीजों से बचें।

4. व्यायाम और सक्रिय जीवनशैलीः जितना हो सके सक्रिय रहे। अधिक ठंड में घर पर ही व्यायाम करें। शरीर का सक्रिय रहना रक्त संचार बेहतर रखता है।

5. तनाव कम करें और पर्याप्त नींद लेंः तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। ध्यान, गहरी सांस, अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद बीपी नियंत्रित रखने में मदद करती है।

6. शरीर गर्म रखें व हाइड्रेटेड रहेंः पर्याप्त गर्म कपड़े पहने। रक्त गाढ़ा होने से बचाने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहे।

7. अल्कोहल और धूम्रपान से दूरीः नई गाइडलाइन के अनुसार, हाई बीपी वाले धूम्रपान व शराब से पूरी तरह दूर रहें।

40 की दहलीज पार करते ही क्यों दरकने लगती हैं हड्डियां? डॉक्टर से जानें बचाव के अचूक उपाय

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती भीड़, मेट्रो की सीढ़ियों पर बढ़ती हलचल और दफ्तरों के वातानुकूलित कमरों में कंप्यूटर के सामने घंटों बीतते वक्त के बीच एक बहुत बड़ा संकट चुपचाप हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। इसे चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ 'साइलेंट किलर' या 'खामोश दुश्मन' कहते हैं। यह दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी हड्डियों की वह कमजोरी है जो 40 की उम्र पार करते ही एक महामारी की तरह फैल रही है। 'राजधानी चौपाल' की इस विशेष रिपोर्ट में हम आज उस कड़वे सच की पड़ताल करेंगे, जिसे अक्सर हम 'बढ़ती उम्र का तकाजा' या 'काम की थकान' कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो वास्तव में भविष्य की एक बड़ी शारीरिक लाचारी की दस्तक है।

दिल्ली के प्रमुख अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक कुमार मिश्रा (सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल) के अनुसार, हड्डियों की कमजोरी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रातों-रात पैदा होती हो। यह एक अत्यंत धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जो हमारे गलत खानपान, धूप से दूरी और निष्क्रिय जीवनशैली के कारण हमारी नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे 40 की उम्र के बाद हमारा शरीर अपना 'कैल्शियम बैंक' खाली करने लगता है और कैसे आप अपनी जीवनशैली में मामूली सुधार करके इस प्रक्रिया को न केवल रोक सकते हैं, बल्कि अपनी हड्डियों को दोबारा फौलादी भी बना सकते हैं।

हड्डियों के विज्ञान को समझना हमारे लिए सबसे पहला और अनिवार्य कदम होना चाहिए। मानव शरीर का कंकाल तंत्र एक जीवित ऊतक है। यह पत्थर या लकड़ी की तरह निर्जीव नहीं है, बल्कि इसमें हर पल कुछ कोशिकाएं टूटती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को चिकित्सा की भाषा में 'बोन रिमॉडलिंग' कहा जाता है। जन्म से लेकर लगभग 30 साल की उम्र तक, नई हड्डियां बनने की रफ्तार टूटने वाली हड्डियों के मुकाबले बहुत तेज होती है। इस समय को 'पीक बोन मास' का दौर कहा जाता है, यानी इस समय आपकी हड्डियां अपने जीवन के सबसे मजबूत स्तर पर होती हैं।

लेकिन, जैसे ही हम 40 का आंकड़ा पार करते हैं, प्रकृति का चक्र पलट जाता है। अब पुरानी हड्डियों के नष्ट होने की दर बढ़ जाती है और नई हड्डी बनने की दर सुस्त पड़ जाती है। इसे ही हम 'बोन लॉस' कहते हैं। राजधानी चौपाल की टीम ने जब दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम आयु वर्ग के लोगों से बात की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अधिकांश लोग पीठ दर्द, घुटनों की कड़कड़ाहट और जल्दी थकान होने को केवल 'ऑफिस का स्ट्रेस' मानते हैं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा चेतावनी देते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कम होना इसका मुख्य कारण है। अगर हमारी डाइट से खून को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलता, तो हमारा शरीर एक रक्षा तंत्र के तहत हड्डियों से कैल्शियम 'उधार' लेना शुरू कर देता है, जिससे हड्डियां भीतर से पोरस (जालीदार) होने लगती हैं।

इस समस्या के पीछे एक और बड़ा अपराधी है—विटामिन-D की भारी कमी। दिल्ली जैसे महानगर में, जहाँ हम ऊंची इमारतों, एसी कारों और बंद दफ्तरों में अपना 90 प्रतिशत समय बिताते हैं, सूरज की रोशनी हमारे शरीर के लिए एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। विटामिन-D वह चाबी है जो शरीर में कैल्शियम के ताले को खोलती है। इसके बिना आप चाहे जितना भी शाही भोजन कर लें या महंगे सप्लीमेंट खा लें, शरीर उस कैल्शियम को सोख ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि आज 40 की उम्र के बाद हड्डियों का कमजोर होना केवल एक शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर जीवनशैली विकार बन चुका है।

विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक और संवेदनशील है। मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) के दौरान महिलाओं के शरीर में 'एस्ट्रोजेन' नामक हार्मोन का स्तर तेजी से गिर जाता है। यह हार्मोन हड्डियों की मजबूती और डेंसिटी बनाए रखने के लिए एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करता है। जैसे ही यह कवच हटता है, बोन लॉस की प्रक्रिया सामान्य के मुकाबले कई गुना तेज हो जाती है। राजधानी चौपाल के सर्वेक्षण में पाया गया कि 40 पार कर चुकी हर तीन में से दो महिलाएं किसी न किसी प्रकार के जोड़ों के दर्द से जूझ रही हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में वे इसे गंभीरता से नहीं लेतीं।

अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं? इसके लिए हमें शरीर द्वारा दिए जाने वाले उन 10 गुप्त संकेतों को समझना होगा जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला संकेत है कद का कम होना। अगर आपको महसूस होता है कि आपकी ऊंचाई पिछले कुछ वर्षों में एक या दो इंच कम हो गई है, तो यह रीढ़ की हड्डियों के आपस में दबने का संकेत है। इसी तरह, अगर आपका पोस्चर झुक गया है और कंधे आगे की ओर लटकने लगे हैं, तो समझिए कि रीढ़ की हड्डी अपनी मूल मजबूती खो रही है।

अन्य संकेतों में हाथ की पकड़ का कमजोर होना भी शामिल है। अगर आपको बोतल का ढक्कन खोलने या बाजार का थैला उठाने में पहले के मुकाबले ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, तो यह हड्डियों और मांसपेशियों की संयुक्त कमजोरी का लक्षण है। इसके अलावा, मसूड़ों की पकड़ ढीली होना, नाखूनों का बार-बार बीच से चटक जाना, और मामूली झटके या गिरने पर भी फ्रैक्चर हो जाना हड्डियों के खोखलेपन का सीधा प्रमाण है। अगर आपको बिना किसी चोट के पीठ या गर्दन में पुराना और धीमा दर्द बना रहता है, तो इसे केवल मांसपेशियों की समस्या समझना भारी भूल हो सकती है। राजधानी चौपाल की इस पड़ताल में 'हाई रिस्क ग्रुप' की पहचान भी की गई है। वे लोग जो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, जो स्मोकिंग या अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, जिनका वजन सामान्य से बहुत कम (लो BMI) है, या जिनके परिवार में हड्डियों की बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही, वे मरीज जो लंबे समय से थायराइड, स्टेरॉयड या किडनी की बीमारियों की दवाएं ले रहे हैं, उनकी हड्डियों पर दवाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ना लगभग निश्चित होता है। इन लोगों को अपनी बोन हेल्थ का नियमित मेडिकल एसेसमेंट करवाना चाहिए।

हड्डियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए केवल लक्षणों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सलाह देते हैं कि 40 के बाद कम से कम एक बार 'स्कैन' जरूर करवाना चाहिए। यह टेस्ट एक्स-रे की तरह ही सरल होता है लेकिन यह आपकी हड्डियों के घनत्व का सटीक स्कोर बताता है।

10 जीवन रक्षक टिप्स

- **कैल्शियम का भरपूर स्रोतः** अपनी डाइट में दूध, दही और पनीर के साथ-साथ रागी, सोयाबीन और गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। एक वयस्क को दिनभर में लगभग 1000-1200mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है।
- **धूप से नाता जोड़ेंः** विटामिन-D के लिए सुबह की कोमल धूप में कम से कम 20 मिनट बिताने का नियम बनाएं। याद रहे, खिड़की के कांच के पीछे बैठने से लाभ नहीं मिलता, इसके लिए सीधा संपर्क जरूरी है।
- **प्रोटीन का सही संतुलनः** हड्डियां केवल कैल्शियम से नहीं, बल्कि प्रोटीन के एक जटिल जाल से बनी होती हैं। इसलिए दालें, सोया पनीर (Tofu) और अंडे का सेवन हड्डियों की संरचना को मजबूती देता है।
- **वेट-बियरिंग एक्सरसाइजः** केवल टहलना काफी नहीं है। हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। जब मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, तो हड्डियां खुद को और मजबूत बनाने के लिए उत्तेजित होती हैं।
- **नमक पर कड़ा नियंत्रणः** ज्यादा नमक पेशाब के जरिए कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल देता है। टेबल सॉल्ट का उपयोग न्यूनतम करें और प्रोसेस्ड फूड से बचें।
- **कैफीन और कोला से दूरीः** दिन भर में बार-बार चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन हड्डियों के घनत्व को कम करता है। इनमें मौजूद फास्फोरिक एसिड कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है।
- **मैग्नीशियम और पोटेशियमः** कद्दू के बीज, केले और मेवे खाएं। ये पोषक तत्व कैल्शियम को हड्डियों के अंदर 'लॉक' करने का काम करते हैं।
- **पोस्चर (मुद्रा) सुधारेंः** कंप्यूटर या मोबाइल के सामने झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। बैठते समय कमर सीधी रखने का अभ्यास करें।
- **नशा त्यागेंः** धूम्रपान और शराब हड्डियों के निर्माण करने वाले सेल्स को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं और बोन लॉस की रफ्तार बढ़ा देते हैं।
- **नियमित मेडिकल चेकअपः** 45 साल की उम्र के बाद हर दो साल में एक बार बोन डेंसिटी की जांच करवाएं ताकि किसी भी समस्या का शुरुआती चरण में ही पता चल सके।

श्रीखंड का पाइनएपल ट्विस्ट

...इस गर्मी चखें पारंपरिक स्वाद ऐसा कि भूल न पाएंगे!

जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, दिल्ली की तपती दोपहरों में कुछ ठंडा और मीठा खाने की तलब बढ़ना लाजिमी है। उत्तर भारत में वैसे तो कुल्फी और फालूदा का राज चलता है, लेकिन जब बात सेहत और स्वाद के संगम की आती है, तो पश्चिम भारत का 'श्रीखंड' बाजी मार ले जाता है। आज 'राजधानी चौपाल' की रसोई में हम साधारण श्रीखंड की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लेकर आए हैं एक ऐसी फ्यूजन रेसिपी जो आपके जायके को एक नए सफर पर ले जाएगी— पाइनएपल श्रीखंड।

अक्सर हम केसर-इलायची या फिर आम का 'आम्रखंड' खाते हैं, लेकिन अनानास (पाइनएपल) की खटास और दही की मिठास जब एक साथ मिलती है, तो वह स्वाद का ऐसा 'धमाका' करती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए जानते हैं, कैसे आप अपने घर में इस शाही डिश को तैयार कर सकते हैं।

सामग्री का सही चुनावः स्वाद की पहली सीढ़ी

किसी भी व्यंजन की सफलता उसकी सामग्री की शुद्धता पर निर्भर करती है। पाइनएपल श्रीखंड बनाने के लिए आपको नीचे दी गई चीजों की जरूरत होगीः

- **गाढ़ा दहीः** 2 कप (कोशिश करें कि दही ताजा हो और ज्यादा खट्टा न हो)।
- **ताजा पाइनएपल प्यूरीः** 2 कप (पके हुए मीठे अनानास का इस्तेमाल करें)।
- **चीनीः** 1/2 कप या स्वादानुसार (बूरा या पिसी चीनी बेहतर घुलेगी)।
- **इलायची पाउडरः** 1/2 छोटा चम्मच (ताजी कुटी हुई इलायची की खुशबू बेमिसाल होती है)।
- **केसर के धागेः** 2 बड़े चम्मच (दूध में भिगोए हुए, जो एक शाही रंग और सुगंध देंगे)।
- **पीला फूड कलरः** एक चुटकी (यह वैकल्पिक है, लेकिन बाजार जैसा लुक देने के लिए अच्छा रहता है)।
- **कटे हुए मेवेः** सजाने के लिए बादाम और पिस्ते की कतरन।

बनाने की विधिः स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

- **अनानास की तैयारी** : सबसे पहले एक अच्छी तरह पका हुआ और खुशबूदार अनानास लें। उसे छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर एक महीन प्यूरी तैयार कर लें। याद रहे, प्यूरी में बड़े टुकड़े न रहें, वरना श्रीखंड की 'क्रीमी' बनावट में बाधा आएगी। इस प्यूरी को एक बाउल में निकाल कर एक तरफ रख दें।
- **चौपाल टिपः** अगर आप थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो प्यूरी को हल्का सा आंच पर 2 मिनट के लिए चीनी के साथ पका सकते हैं, इससे पाइनएपल का स्वाद और भी गहरा हो जाता है।
- **'चक्का' तैयार करना** : श्रीखंड की जान उसका गाढ़ापन होता है। इसके लिए 2 कप दही को एक साफ मलमल के कपड़े में बांधें और इसे कहीं ऊंचाई पर करीब 30 से 45 मिनट के लिए लटका दें। इससे दही का सारा अतिरिक्त पानी निकल जाएगा और आपको मिलेगा बिल्कुल मलाई जैसा 'चक्का'।
- **मिश्रण का संगम** : अब एक बड़ा और गहरा बाउल लें। इसमें वह गाढ़ा दही (चक्का) डालें। अब इसमें तैयार की गई पाइनएपल प्यूरी, पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और केसर वाला दूध मिलाएं। इन सबको अच्छी तरह से फेंटना सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप इसे हाथ से या इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटते हैं, तो श्रीखंड में एक खास तरह की चमक और हल्कापन आ जाता है।
- **रंग और बनावट** : यदि आपको लगता है कि मिश्रण बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो आप इसमें एक-दो चम्मच ठंडा दूध मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, श्रीखंड की पहचान उसका गाढ़ा और क्रीमी होना ही है। इस स्तर पर आप चाहें तो एक चुटकी पीला फूड कलर डाल सकते हैं ताकि यह दिखने में और भी आकर्षक लगे।

जब दिखेगा अच्छा, तो बिकेगा अच्छा!

अब आपका पाइनएपल श्रीखंड लगभग तैयार है, लेकिन असली जादू बाकी है। इस मिश्रण को एक एयरटाइट डिब्बे में रखें और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने दें। गर्मी के मौसम में श्रीखंड जितना ठंडा होगा, उतना ही उसका स्वाद निखर कर आएगा। जब मेहमान आने वाले हों या खाने के बाद मीठे का समय हो, तो इसे छोटे कांच के कटोरे या मिट्टी के कुल्हड़ों में निकालें। ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर के कुछ धागे छिड़कें। अनानास का एक छोटा टुकड़ा किनारे पर लगाकर इसे सजाएं।

केदारनाथ धाम की यात्रा करने वालों में 80% युवा : कपाट खुलते ही दिखा नया ट्रेंड; पहले सिर्फ बुजुर्ग, अब 'जेन जी' में बढ़ रहा क्रेज

रुद्रप्रयाग (राजधानी चौपाल) | केदारनाथ धाम में इस बार दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में करीब 80% युवा शामिल हैं। पहले जहां चारधाम यात्रा बुजुर्गों तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब युवाओं खासकर 'जेन जी' की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। धर्म और आस्था के जानकार इसे नई पीढ़ी के सनातन परंपराओं की ओर बढ़ते रुझान के रूप में देख रहे हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलते ही देशभर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले ही दिन करीब 38 हजार तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। आंकड़ों के मुताबिक, इनमें 23,978 पुरुष, 12,777 महिलाएं और 1,245 बच्चे शामिल रहे। जिला प्रशासन के अनुसार, कुल श्रद्धालुओं में लगभग 30,400 युवा रहे, यानी करीब 75–80 प्रतिशत। यह संकेत देता है कि न सिर्फ आस्था का ट्रेंड बदला है, बल्कि धार्मिक यात्राओं में युवाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं, दूसरे दिन दर्शन करने वालों की संख्या 25 हजार के पार पहुंच गई। इस तरह महज दो दिनों में 63 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में पहुंच चुके हैं, जो यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह को दर्शाता है।

बुजुर्गों से आगे बढ़े युवा, 18 किमी पैदल भी नहीं रोक पा रहा उत्साह : परंपरागत रूप से चारधाम यात्रा को मोक्ष प्राप्ति से जोड़ा जाता रहा है और इसमें अधिकतर बुजुर्ग ही शामिल होते थे। आम धारणा थी कि लोग 60 वर्ष की आयु के बाद तीर्थयात्रा पर निकलते हैं, लेकिन अब यह सोच तेजी से बदल रही है। अब युवा भी उतनी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में युवा श्रद्धालु गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक करीब 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। कठिन चढ़ाई और चुनौतीपूर्ण रास्ते के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, युवाओं खासकर 'जेन जी' का धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ता रुझान आने वाले समय में सनातन परंपराओं के लिए सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि नई पीढ़ी आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों और आस्था से भी मजबूती से जुड़ रही है।

भीड़ प्रबंधन के लिए टोकन व्यवस्था लागू : केदारनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था सुचारु रखने के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू किया है। सीओ पुलिस विकास पुंडीर के अनुसार, श्रद्धालुओं को निर्धारित समय के अनुसार दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं, जिससे भीड़ नियंत्रित और सुरक्षित बनी हुई है। डीएम विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर खुद धाम में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं।

अब जानिए कौन होते हैं 'जेन जी'

'जेन जी' यानी Generation Z उस पीढ़ी को कहा जाता है, जिसका जन्म आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह वही पीढ़ी है जो बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में पली-बढ़ी है, इसलिए इन्हें डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है। जेन जी के युवाओं के लिए इंटरनेट और डिजिटल दुनिया कोई नई चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये पढ़ाई, मनोरंजन, काम और सामाजिक जुड़ाव हर चीज में तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हाल के वर्षों में यह देखने को मिला है कि जेन जी सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की ओर भी लौट रही है। केदारनाथ जैसे तीर्थस्थलों पर इनकी बढ़ती मौजूदगी इसी बदलाव का संकेत है।

बद्रीनाथ धाम में पहले ही दिन 14 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किदए दर्शन

भू-वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पहले 24 घंटे में ही 14,091 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीविशाल के दर्शन किए। इनमें 8,999 पुरुष, 3,994 महिलाएं और 1,098 बच्चे शामिल रहे। भीड़ को देखते हुए चमोली प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों अधिकारी यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं।

▪ **बद्रीनाथ में लोक संस्कृति की झलक, जागरों पर झूमे श्रद्धालु** : गोपेश्वर में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर आस्था के साथ लोक संस्कृति का संगम देखने को मिला। माणा और बामणी गांव की महिलाओं ने पारंपरिक जागरों के साथ झुमैलो नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान सेना के जवानों ने बैंड की मधुर धुनों के साथ भगवान बदरीनाथ का अर्चन किया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को 1.01 करोड़ का दान

प्रसिद्ध उद्योगपति और श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के वरिष्ठ सदस्य महेंद्र शर्मा ने मंदिर समिति को 1 करोड़ 1 लाख रुपये का दान दिया है। बदरीनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह राशि चेक के माध्यम से भेंट की। इस अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उनका स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया।

हेमंत द्विवेदी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी महेंद्र शर्मा देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल हैं और पिछले एक दशक से मंदिर समिति के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा द्वारा देशभर के तीर्थस्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दिया जाता रहा है। उनका यह दान भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो अन्य श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणादायक है। महेन्द्र शर्मा ने कहा कि भगवान बदरीनाथ और केदारनाथ के प्रति उनकी गहरी आस्था है और यह दान उसी श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंदिर समिति इस राशि का उपयोग धार्मिक कार्यों और श्रद्धालुओं की सेवा में करेगी।

गंगोत्री में गंगा सप्तमी पर विशेष पूजा, श्रृंगार रूप में होंगे दर्शन : गंगोत्री धाम में गंगा सप्तमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां गंगा की निर्वाण मूर्ति का महाभिषेक और भव्य श्रृंगार किया गया। अब कपाट बंद होने तक श्रद्धालु मां गंगा के श्रृंगार रूप में ही दर्शन करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन मां गंगा का अवतरण हुआ था।

रिफाइनरी हादसा...साजिश, चूक या उद्घाटन की जल्दबाजी तो नहीं?: 'हड़बड़ी की आग'... 8 साल में प्रोजेक्ट 90.4 प्रतिशत पूरा; 3 माह में 9.6 प्रतिशत कैसे?

जयपुर /बाड़मेर (राजधानी चौपाल) | पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग ने निर्माण और संचालन की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेट्रोलियम विभाग के अनुसार दिसंबर 2025 तक 90.4% और 20 अप्रैल तक करीब 92% काम ही पूरा हुआ था, जबकि इसी बीच उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। 2018 में शुरू प्रोजेक्ट को 90% तक पहुंचने में 8 साल लगे। ऐसे में सवाल है कि क्या 9.6% शेष काम और सुरक्षा परीक्षण पूरे किए बिना ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

विशेषज्ञों के मुताबिक 90% से 100% का 'कमीशनिंग फेज' सबसे संवेदनशील होता है, जहां लीकेज, प्रेशर और सिस्टम फेल होने का खतरा रहता है। दिसंबर तक 9 में से 8 यूनिट्स का मैकेनिकल काम पूरा था, लेकिन सीडीयू यूनिट में पहली बार कच्चा तेल डालने के दौरान जोखिम सबसे ज्यादा होता है।

मानक के अनुसार किसी यूनिट को संचालन योग्य तभी माना जाता है, जब वह 72 घंटे तक लगातार बिना रुकावट चले। जबकि आग के समय यूनिट ट्रायल पर थी और 13 में से 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट्स अब भी निर्माणाधीन थीं। जिस हिस्से में आग लगी, वह मैकेनिकली तैयार था, लेकिन ऑपरेशन के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित नहीं, यही अब जांच का सबसे बड़ा बिंदु है।

वार्निंग सिस्टम साइलेंट, सेंसर भी फेल; जांच कंट्रोल रूम के आखिरी 48 घंटे पर टिकी

रिफाइनरी के उद्घाटन से महज 20 घंटे पहले लगी आग अब सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि संदेहों का केंद्र बन गई है। करोड़ों के हाईटेक सेफ्टी सिस्टम के बावजूद अर्ली वार्निंग का साइलेंट रहना सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। NIA ने कंट्रोल रूम के आखिरी 48 घंटे को खंगालना शुरू कर दिया है। फोकस इस पर है कि यह तकनीकी चूक थी या सिस्टम से छेड़छाड़ की गई। एनआईए और गृह मंत्रालय की टीम ने पीएम दौरे से पहले के 48 घंटे की पूरी टाइमलाइन को जांच के केंद्र में रखा है। कंट्रोल रूम के डेटा लॉग, सीसीटीवी फुटेज और यूनिट में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति की मूवमेंट का विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं, हादसे ने रिफाइनरी के कमर्शियल ऑपरेशन की टाइमलाइन बिगाड़ दी है। 1 जुलाई 2026 से उत्पादन शुरू होना था, लेकिन अब प्रभावित यूनिट को दोबारा खड़ा करने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं। पहले ही 79,450 करोड़ तक पहुंच चुकी परियोजना लागत में और बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

▪ **फायर सप्रेशन सिस्टम** : रिफाइनरी में लगे ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम और सुरक्षा सेंसर अब जांच के घेरे में हैं। सेंट्रल फॉर हाई टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ पूरे सिस्टम का तकनीकी ऑडिट करेंगे।

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और अकासा के विमान टकराए

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट और अकासा एयर के विमान आपस में टकरा गए। घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक अकासा का विमान हैदराबाद जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसी समय लेह से आया स्पाइसजेट का विमान उससे टकरा गया। हादसे में स्पाइसजेट के दाहिने पंख का हिस्सा अकासा के बाएं तरफ के पिछले पंख में जा घुसा। घटना के बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने दोनों प्लेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया। हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं लगी। घटना के बाद स्पाइसजेट और अकासा के प्लेन दिल्ली में ही खड़े कर दिए गए हैं, यानी इन्हें अगली उड़ान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। घटना की जांच की जा रही है।

अकासा एयरलाइंस बोली- हमारा विमान पार्किंग एरिया में खड़ा था : अकासा एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि अकासा एयर की दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट पार्किंग एरिया में खड़ी थी, तभी दूसरे विमान ने उसे टक्कर मार दी। हमारी टीम यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद भेजने के लिए दूसरा इंतजाम कर रही है। विमानों की टक्कर के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय

(MOCA) ने बताया कि घटना की जांच होने तक संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) अधिकारी और स्पाइसजेट के पायलटों को रोस्टर से हटा दिया गया है।

RNI No. HARHIN/25/A3341, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं संपादक राहुल कुमार द्वारा सूचना प्रिंटर्स 33एस मॉडल टाउन, हिसार से छपवाकर कार्यालय आदमपुर मंडी हिसार, (किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार न्यायालय होगा)।
संपादक : राहुल कुमार, फोन : 9306813001, e-mail : rajdhanichoupal@gmail.com, प्रकाशन स्थल : मकान संख्या : 114, शांति पार्क के पास, मंडी आदमपुर, हिसार (हरियाणा)